



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 22, 2018/अग्रहायण 1, 1940

No. 372] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 2018/AGRAHAYANA 1, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2018

अंतिम जांच परिणाम

**विषय :** बंगलादेश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए 'जूट उत्पादों' अर्थात् - जूट यार्न/ ट्वाइन (अनेक बार मोड़ा हुआ/ केबल्ड किया हुआ और एकल), हैसियन फेब्रिक और जूट सेकिंग बैग के आयातों लगाये गये पाटनरोधी शुल्क के संबंध में सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के नियम 22 के अंतर्गत 1.1.2018 को आरंभ किए गए सेकिंग बैग के संबंध में मैसर्स जनता जूट मिल्स (पी) मिलकर किये गये अनुरोध के अनुसार न्यू शिप्पर समीक्षा।

**फा.सं. 7/10/2017-डीजीएडी.**—सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है (इसके पश्चात अधिनियम के रूप में भी संदर्भित) और उसके सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया (इसके पश्चात नियमावली के रूप में भी संदर्भित) के संबंध;

**क. मामले की पृष्ठभूमि**

- जबकि, मूल पाटनरोधी जांच में, निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके पश्चात प्राधिकारी के रूप में भी संदर्भित) ने दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 से अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/19/2015 - डी जी ए डी के माध्यम से सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 69 के अंतर्गत आने वाले बंगलादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "जूट उत्पादों" अर्थात् जूट यार्न/ ट्वाइन (अनेक बार मोड़ा हुआ/ केबल्ड किया हुआ और एकल), हैसियन फेब्रिक और जूट सेकिंग बैग के आयातों पर पाटनरोधी लगाये जाने की सिफारिश की। केंद्र सरकार ने दिनांक 5 जनवरी, 2017 के अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (ए डी डी)-सीमा शुल्क और दिनांक 3 अप्रैल, 2017 के सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 11/2017 - सीमा शुल्क (ए डी डी) के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क अधिसूचित किया।

3. मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि. (उत्पादक और निर्यातक) ने बंगलादेश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए सेकिंग बैग के आयातों के संबंध में अलग अलग पाटन मार्जिन का दावा करते हुए एक नई शिप्पर समीक्षा (एन एस आर) का अनुरोध करते हुए सीमा प्रशुल्क अधिनियम के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के संबंध में नई शिप्पर समीक्षा (एन एस आर) के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जिसका निर्यात उनके द्वारा मूल जांच की जांच अवधि के दौरान नहीं किया गया था जिसमें पाटनरोधी उपाय दिनांक 3 अप्रैल, 2017 के सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 11/2017-सीमा शुल्क (ए डी डी) के माध्यम से लगाया गया है।
4. प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत दिए गए शर्तों से प्रथमदृश्या संतुष्ट होने पर मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि. (उत्पादक) के संबंध में बंगलादेश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए जूट सेकिंग बैग के पाटित आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्कों को आरोपित करने के उद्देश्य से अलग अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए दिनांक 1 जनवरी, 2018 के अधिसूचना संख्या 7/10/2017- डी जी ए डी के माध्यम से एक नई शिप्पर समीक्षा जांच आरंभ की।
5. वित्त मंत्रालय ने दिनांक 30 मई, 2018 के अधिसूचना संख्या 30/2018 - सीमा शुल्क (ए डी डी) के माध्यम से उपरोक्त एन एस आर जांच को पूरा किये जाने तक मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि. द्वारा किए गए संबद्ध वस्तुओं के सभी निर्यातों पर अनंतिम आकलन को अधिसूचित किया।
6. इस नई शिप्पर समस्या के उद्देश्य से जांच की अवधि 1 जनवरी, 2017 से 30 जून, 2018 के रूप में तय की गई थी।

#### ख. प्रक्रिया

7. नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन वर्तमान जांच के संबंध में किया गया है :
  - (i) प्राधिकारी ने संबद्ध एन एस आर पाटनरोधी जांच आरंभ करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 1 जनवरी, 2018 के अधिसूचना संख्या 7/10/2017 - डी जी ए डी के माध्यम से एक आम सूचना जारी की।
  - (ii) प्राधिकारी ने निर्यातक की प्रश्नावली की एक प्रति के साथ साथ आवेदक को जांच आरंभ करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें जांच की अवधि के समाप्त होने के बाद निर्धारित प्रश्नावली में अपने विचारों को लिखित रूप में अवगत कराने तथा संबंधित आंकड़ प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया।
  - (iii) प्राधिकारी ने भारत में बंगलादेश के उच्चायोग को जांच आरंभन संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भी अग्रेषित की।
  - (iv) प्राधिकारी ने भारत में ज्ञात घरेलू उत्पादकों को जांच आरंभन संबंधी अधिसूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अवसर दिया।
  - (v) जांच आरंभन संबंधी अधिसूचना के उत्तर में, मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि., जो एन एस आर के लिए आवेदक है, द्वारा प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया गया था।
  - (vi) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुरोधों/ सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
  - (vii) प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने के लिए और उसके बाद लिखित रूप में अनुरोध करने के लिए अवसर उपलब्ध कराने हेतु 6 सितम्बर, 2018 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों/ सूचना के संबंध में खंडन प्रतिउत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त अनुरोधों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।
  - (viii) इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी संगत अनुरोधों/ टिप्पणियों पर विचार किया गया है और उसे इस अंतिम जांच परिणाम में शामिल किया गया है।

#### ग. विचाराधीन उत्पाद

8. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद 'जूट उत्पाद' है जिसमें जूट यार्न/ ट्वाइन (अनेक बार मोड़ा हुआ/ केबल्ड किया हुआ और एकल), हैसियन फेब्रिक और जूट सेकिंग बैग शामिल है। प्राधिकारी ने मूल जांच में उत्पादकों को जूट उत्पादों के प्रत्येक प्रकार के लिए अलग अलग शुल्क की सिफारिश की थी। यह जांच दिनांक 1.1.2018 के जांच आरंभन संबंधी

अधिसूचना के पैरा 1 में यथा उल्लिखित मूल जांच में विचार किए गए सेकिंग बैग अर्थात् विचाराधीन उत्पाद के उत्पाद प्रकारों में से एक मात्र के निर्यात से संबंधित है।

**घ. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध :**

**9. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध :**

- i. आवेदक ने पर्याप्त और आवश्यक सूचना उपलब्ध कराये बिना वर्तमान जांच आरंभन की मांग की है। याचिका में यह दर्शाने के लिए सूचना और साक्ष्य नहीं है कि आवेदक नियम 22 की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आवेदक को यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि यह एक वास्तविक निर्यातक है जिसने वास्तव में बिक्री की है, मूल जांच में वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है और यह संबद्ध वस्तुओं जिस पर शुल्क लगता है, का उत्पादक/ निर्यातक से संबंधित नहीं है।
- ii. आवेदक ने 31 अगस्त, 2018 को प्रश्नावली का उत्तर दायर किया जबकि प्राधिकारी ने 25 अप्रैल को एन एस आर जांच के लिए नई प्रश्नावली प्रपत्र बनाया है। पर्याप्त समय लेने के बावजूद, दायर किये गये प्रश्नावली का उत्तर नए प्रपत्र को पूरा नहीं करता है।
- iii. आवेदक ने इसके संबंध में जानकारी नहीं होने को स्वीकार किया है कि क्या इसने मूल जांच के लिए जांच की अवधि के दौरान भारत में निर्यात किया जो यह दर्शाता है कि याचिका में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक ने मूल जांच की जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया। यह जांच कानून के अंतर्गत ऐसी महत्वपूर्ण अपेक्षा को पूरा किये बिना आरंभ की गई है।
- iv. इस आवेदन में कोई भी ऐसी बात यह नहीं दर्शाती है कि यह दर्शाने की आवश्यकता कि आवेदक निर्यात करने वाले देश में किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं है जो उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अधीन है, को पूरा नहीं किया गया है। नियम 22 की ऐसी महत्वपूर्ण अपेक्षा को नई शिप्पर समीक्षा जांच की मांग करने के पूर्व पूरा नहीं किया गया है। आवेदक इस संबंध में किसी साक्ष्य को उपलब्ध नहीं करा पाये हैं।
- v. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के रूप में बाद की अवधि अर्थात् ऐसी वह अवधि जिसमें नियम 22 के अंतर्गत जांच आरंभ करने तक की बाद की अवधि शामिल है, को चुना। विगत में निर्यातक द्वारा स्वीकार्य रूप से निर्यात किया गया था। उन निर्यातों पर विचार करने के बजाय, प्राधिकारी ने बाद की जांच की अवधि के आधार पर आगे की कार्यवाही करने का विकल्प लिया जो उपयुक्त नहीं है। ऐसे मामले में आवेदक जांच की अवधि के दौरान उच्च कीमतों पर मामूली संख्या में लेन देन कर आंकड़ों में हेर-फेर करने और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने में सक्षम हुए हैं। इस अवधारणा की आलोचना में सेसटेट द्वारा टाइल्स मामले में की गई है।
- vi. विगत में प्राधिकारी ने निर्यात के लिए किए गए ठोस प्रतिबद्धता अथवा किए गए निर्यात के बारे में संतुष्ट होने पर ही नई शिप्पर समीक्षा जांच आरंभ की है। कानून के अंतर्गत अपेक्षित साक्ष्य जांच की अवधि के बाद किए गए निर्यात और भारत में इस उत्पाद की बिक्री के लिए रद्द न किए जाने योग्य संविदागत करारों के साथ साथ जांच की अवधि के पूर्व किए गए निर्यात को सिद्ध करता है। हालांकि, इनमें से किसी का उल्लेख आवेदन में नहीं किया गया है।
- vii. जांच की अवधि के दौरान आवेदक द्वारा किया गया निर्यात विश्वसनीय तरीके से वाणिज्यिक लेन देन होना चाहिए ताकि पाटन के मार्जिन के लिए आधार बन सके। यह देखा जाना है कि क्या विचाराधीन बिक्री प्रतिकात्मक है और यह नई शिप्पर की भावी बिक्री का द्योतक होगा। मूल्य और मात्रा दोनों के मामले में इन बिक्रियों की असलियत/ वास्तविकता की जांच की जानी चाहिए।
- viii. यू. एस. ए. में 'वास्तविक बिक्री' की अवधारणा पी ओ आर के दौरान गलत लेन देन कर शुल्क से बचने के प्रयासों को रोकने के लिए शुरू किया गया था। यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया था कि पी ओ आर के दौरान लेन देन "शिप्पर की भावी वाणिज्यिक प्रथा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिप्पर शुल्क संबंधी आदेश को नाकाम करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं", को द्योतक है। उद्देश्य 'प्रत्येक बिक्री की इसकी व्यापारिक तर्कसंगतता की जांच करना'। इस अवधारणा को 2015 के व्यापार आसान करने और व्यापार प्रवर्तन अधिनियम की धारा 433 में संहिताबद्ध किया गया था। जहां वास्तविक बिक्री का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण कारकों पर विचार किया गया है।
- ix. शुरू की गई अलग अलग एन एस आर जांचों को एक साथ मिला दिया जाना चाहिए क्योंकि कानून के अंतर्गत अपेक्षा "आवधिक समीक्षा करना" है, इसका आशय यह हुआ कि आवेदनों को तय किए गए अथवा

निर्धारित अंतरालों पर स्वीकार किया जाना चाहिए और न कि जिस प्रकार से और जब आवेदन प्रस्तुत किया गया हो। यह इन्हें एक साथ मिलाने के लिए प्रशासनिक सुविधा भी होगी।

- X. आवेदक ने अलग अलग पाटन मार्जिन की स्वीकृति के लिए अपने मामले को सिद्ध नहीं किया गया है और जिसके अभाव में मूल जांच में नमूने में शामिल न किए गए सहयोग करने वाली कंपनियों को दिए गए भारित औसत शुल्क दिए जा सकते हैं, क्योंकि मूल जांच में नमूना लेना शामिल था।
- xi. नियम 17 के अंतर्गत, निर्यातकों को अपने पाटन मार्जिन का अधिकार प्राप्त है लेकिन नियम 17 के अंतर्गत यह अधिकार नियम 17 के अंतर्गत नमूने के संबंध में आगे के प्रावधान द्वारा अधिश्रमित/ कम हो जाता है, जिसमें प्राधिकारी को प्रत्येक ज्ञात निर्यातक/ उत्पादक के लिए अलग अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं करने का अधिकार प्राप्त है।
- xii. अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण मात्र से प्राधिकारी पर बोझ बढ़ जाता है और उत्पादक की श्रेणियों तथा उत्पादकों की संख्या पर विचार करते हुए लगभग 855 संभावित समुच्चय हैं जिनमें इन वस्तुओं का निर्यात भारत में किया जा सकता था। इन सभी माध्यमों का उपयोग मूल जांच की जांच की अवधि में नहीं किया गया था और इस कारण से निर्यात के लिए काफी संख्या में माध्यम उपलब्ध हैं। प्रत्येक नए शिप्पर के लिए अलग अलग मार्जिन का निर्धारण करना अधिकारी पर बहुत बड़ा बोझ होगा।
- xiii. नियम 22 में इस वाक्यांश 'समय समय पर' का प्रावधान है जिसका सामान्य आशय यह है कि निर्धारित अंतरालों पर ऐसा किया जाए जिससे वर्तमान जांच में आरंभ किए गए समीक्षाओं की संख्या को मिलाने का संकेत मिलता है।
- xiv. सहयोग करने वाले नमूने न लिये गये उत्पादकों को नई शिप्पर की तुलना में हानि नहीं हो सकती है क्योंकि उन्हें अलग अलग मार्जिन नहीं दिया गया था।
- xv. ऐसा कोई तर्क की उनके अपने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर अलग अलग पाटन मार्जिन नहीं देने के फलस्वरूप पाटन मार्जिन में बढ़ोतरी होगी और इन निर्यातकों को पाटनरोधी शुल्क की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा का भुगतान करना पड़ सकता है, जो भुगतान उस स्थिति में किया जाता यदि प्राधिकारी अपने निजी आंकड़ों पर विचार किया होता जिसका आशय यह होता है कि नमूने लेने संबंधी कानून गैर कानूनी है। ऐसी स्थिति जब निर्यातक को अपने निजी पाटन मार्जिन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता हो, का समाधान समीक्षा कानूनों में किया गया है।
- xvi. यदि पाटन मार्जिन का निर्धारण उनके आंकड़ों के आधार पर नहीं किया जाता हो तब निर्यातकों को कोई हानि नहीं होती है और ऐसे निर्यातक नमूने लिए गए सहयोगी निर्यातकों के लिए मूल रूप में निर्धारित पाटनरोधी शुल्क के आधार पर पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन हैं।
- xvii. प्राधिकारी को उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा सूचना दी गई आयात की मात्राओं पर विचार करना और उनकी तुलना करनी होती है और उनकी तुलना मूल जांच के समय उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा सूचित किए गए आयात मात्राओं से की जानी होती है। इन निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा अलग अलग प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर अलग अलग सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए विचार किए गए निर्यातों की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है।
- xviii. क्योंकि निर्यात कीमत वह कीमत है जिस पर इन वस्तुओं का निर्यात भारतीय बाजार में खपत के लिए किया गया है, वह कीमत जिस पर भारत में अलग अलग क्रेताओं ने संबद्ध देश से अलग अलग आपूर्तिकर्ताओं से इन वस्तुओं की खरीद की है, बहुत अधिक अलग अलग नहीं हो सकती है। संबद्ध देश की भौगोलिक रूप से नजदीक होने पर विचार करते हुए बंगलादेश में अलग अलग उत्पादकों द्वारा किए गए खर्चों में बहुत अधिक अंतर नहीं हो सकता है। वह यूरोपीय यूनियन की प्रथा भी है और नए आपूर्तिकर्ताओं को मार्जिन देने की भी वही प्रथा है जिसे मूल जांच में नमूने न लिए सहयोगी निर्यातकों को दी गई थी और उसका पालन वर्तमान जांच में किया गया जाए।
- xix. प्राधिकारी को इस बात का निर्धारण करने के लिए जांच के परिणाम तक सीमित करना चाहिए कि क्या उत्तर देने वाले निर्यातक नियम 22 के अभिप्राय से एक नई शिप्पर हैं।
- xx. डब्ल्यू टी ओ के पैनल के रिपोर्ट के आधार पर आवेदक का तर्क गलत है। पैनल की उस रिपोर्ट में जांच में सेम्पल भी नहीं लिया गया था। इसमें केवल यह प्रावधान है कि करार के अनुच्छेद 9.5 में किसी क्रॉस संदर्भ का न होना यह दर्शाता है कि अनुच्छेद 9.4 के अनुसार तटस्थ मार्जिन देकर अवशिष्ट शुल्क मार्जिन की

गणना करने का दायित्व प्राधिकारी पर नहीं है। डब्ल्यू टी ओ के पैनेल की टिप्पणी कानून के अंतर्गत प्राधिकारी पर दायित्व और वह भी मूल जांच में दायित्व के संबंध में थी।

- xxi. आवेदक ने तथ्यों को दबाने की कोशिश की है और मूल जांच में अपूर्ण सूचना प्रस्तुत की है। आवेदक का एक संबंधित प्रतिष्ठान, 'साद जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड' है। यह दावा किया गया है कि यह जूट सेकिंग बैग का उत्पादन नहीं करता है बल्कि केवल जूट यार्न का उत्पादन करता है और इस कारण इसने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तु नहीं किया है। इस प्रकार की सूचना को मूल जांच में प्रकट नहीं किया गया था। जूट यार्न/ट्वाइन का एक उत्पादक/निर्यातक होने के बावजूद, यह पूर्व की जांच में प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया। एक उत्पादक होने का दावा करने के बावजूद, संबंधित पक्षकार ने मूल जांच में भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। मूल जांच में निर्यातक ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया कि इसकी कोई संबद्ध अथवा सहायक कंपनी नहीं है जो विचाराधीन उत्पाद में शामिल हो।
- xxii. याचिकाकर्ता की सेकिंग बैग की कोई घेरलू बिक्री नहीं है और यह भारत में मूल जांच के दौरान इसका निर्यात नहीं किया फिर भी इसका भारत में बहुत अधिक व्यापारिक हित है।
- xxiii. आवेदक ने बिना किसी सही कारण के अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया। इसने इस प्रकार के आंकड़ों को गोपनीय माना जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इसने भारतीय ग्राहकों को किए गए जांच के अधीन उत्पाद का निर्यात, उत्पादन किए गए उत्पाद और निर्यात किए गए उत्पाद तथा संबंधित पक्षकारों की सूचना से संबंधित निर्यात दस्तावेज, स्वामित्व का विवरण, ज्ञापन एवं संस्था के अंतर नियम जैसी सूचना पर गोपनीयता की मांग की। याचिका और प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय पाठ पाटनरोधी नियमावली और व्यापार नोटिस 1/2013 के अंतर्गत गोपनीयता संबंधी अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है।
- xxiv. नियम 22 के अंतर्गत यह सिद्ध करने की अपेक्षाओं कि इसने जांच की अवधि में इस उत्पाद का निर्यात नहीं किया है और यह उत्पाद पर शुल्कों के अध्यधीन निर्यात करने वाले देश में किसी निर्यातक/उत्पादक से संबंधित नहीं है, को आवेदन में पूरा नहीं किया गया है और यह केवल कथनों पर आधारित है।
- xxv. आवेदन ने विचाराधीन उत्पाद में औपचारिक व्यापार किया है और यह प्राधिकारी से यह चाहता है कि वे अलग अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करें।
- xxvi. आवेदक एक नई शिप्पर नहीं है और इसने मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है और इस पर विचाराधीन उत्पाद के एक प्रकार पर पाटनरोधी शुल्क लगता है।
- xxvii. क्योंकि प्राधिकारी प्रवंचना संबंधी कार्यवाही की भी जांच कर रहा है अतः इस बात का पता लगाना महत्वपूर्ण है कि क्या आवेदक सेकिंग कपड़े का निर्यात कर रहा है या नहीं। इसे सेकिंग बैग के प्रवंचना किए हुए उत्पाद होने के कारण सेकिंग कपड़े के बारे में भी सूचना अवश्य उपलब्ध करानी चाहिए।
- xxviii. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की उपयुक्तता के संबंध में आवेदक द्वारा कोई सूचना, साक्ष्य और दावा नहीं उपलब्ध कराया गया है। पाटन मार्जिन के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। आवेदक ने अपने आप को प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने तक सीमित रखा है जो मूल जांच के लिए संगत है।
- xxix. किसी भी आयातक ने वर्तमान जांच में उत्तर नहीं दिया है, जिसके फलस्वरूप दावा किये गये निर्यात कीमत की उपयुक्तता सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा, वास्तविक लेन देन जो वर्तमान जांच में महत्वपूर्ण है, भी मौजूद नहीं है।
- xxx. आवेदक ने अपने चिंता के अनुसार भारतीय पाटनरोधी विधान के नियम 22 के अंतर्गत यथा उल्लिखित 'गा' शब्द का सुविधाजनक तरीके से संदर्भ लिया है। हालांकि, 'गा' शब्द को नहीं शिप्पर समीक्षा आरंभ करने के लिए उनमें उल्लिखित शर्तों के साथ पढ़ा जाना है।
- xxxi. यह जांच तब शुरू की जा सकती है जब नई शिप्पर ने यह दर्शाते हुए अपने दायित्व का प्रभावी रूप से निवर्हन किया है कि नियम 22 के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है जिसे वर्तमान मामले में पूरा नहीं किया गया है।

#### 10. **आवेदक निर्यातक द्वारा किया गया अनुरोध :**

- i. नियम 22 में यह प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी नई शिप्पर के लिए समीक्षा करेगा। 'गा' शब्द का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में नई शिप्पर समीक्षा का अनिवार्य आरंभन का प्रावधान है अर्थात् यदि नियम 22 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा कर लिया जाता है तब निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे नई शिप्पर समीक्षा आरंभ करें और इस संबंध में उनके पास कोई विवेकाधिकार नहीं

होता है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग का यह दावा कि नई शिप्पर समीक्षा आरंभ नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वर्तमान मामले में यह उस स्थिति में भी उपयुक्त नहीं है नियम 22 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा कर लिया जाता है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

- ii. पाटनरोधी करार में, अनुच्छेद 9.5 नई शिप्पर समीक्षा को आरंभ करने को अनिवार्य बनाता है। 'गा' शब्द का उपयोग अनुच्छेद 9.5 के अंतर्गत यह दर्शाता है कि जांच करने वाले प्राधिकारी के लिए किसी विवेकाधिकार की कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार से यदि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 के अंतर्गत शर्तों को पूरा कर लिया जाता है तब प्राधिकारी के लिए न केवल समीक्षा करना अनिवार्य हो जाता है बल्कि इस प्रकार के निर्यातक के लिए पाटन की अलग अलग मार्जिन का निर्धारण करना भी अनिवार्य होता है।
- iii. घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि आवेदक को नई शिप्पर समीक्षा के लिए पात्र होने के लिए जांच की अवधि के दौरान किसी भी रूप में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं करना चाहिए था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान उन उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों के आधार पर उत्पाद की प्रत्येक श्रेणी के लिए विभिन्न सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों को शुल्क की अलग अलग दर स्वीकृत की है। यदि किसी उत्पादक/ निर्यातक ने उत्पाद की विशिष्ट श्रेणी का निर्यात नहीं किया होता तब वे उत्पादक उस विशिष्ट श्रेणी के संबंध में शुल्क की शेष दर के अध्यक्षीन होती। प्रतिवादी ने जांच की अवधि के दौरान भारत में जूट यार्न/ ट्वाइन और हैसियन फेब्रिक का निर्यात किया। हालांकि, प्रतिवादी ने जांच की अवधि के दौरान सेकिंग बैग का निर्यात नहीं किया। तदनुसार, मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि. को जूट यार्न/ ट्वाइन और हैसियन फेब्रिक के लिए अलग अलग पाटनरोधी शुल्क दरें मंजूर की गई थीं परंतु सेकिंग बैग के लिए, यह पाटनरोधी शुल्क की शेष दर के अध्यक्षीन थी।
- iv. यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी जांच में तीन अलग अलग उत्पाद श्रेणियां थीं और प्रत्येक उत्पाद श्रेणी को पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के लिए पृथक् रूप से माना गया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति को नहीं देख सके जिसमें किसी विशेष उत्पाद प्रकार का निर्यात किसी उत्पादक/ निर्यातक द्वारा नहीं किया गया था। तदनुसार, यह अंतिम जांच परिणाम में नीचे दिए गए अनुसार विधिवत नोट किया गया था :

*“यदि किसी उत्पाद प्रकार अर्थात् यार्न/ ट्वाइन, सेकिंग बैग अथवा हैसियन फेब्रिक का निर्यात किसी नमूने दिए गए उत्पादक/ निर्यातक द्वारा नहीं किया गया है तब उत्पादकों/ निर्यातकों की शेष श्रेणी के लिए यथा निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन जांच की अवधि के दौरान भारत में निर्यात न किए गए उत्पाद प्रकार के लिए इस प्रकार के उत्पादक/ निर्यातक को दी गई है। कोई भी उत्पादक/ निर्यातक जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया है पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है।”*

- v. अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी की उपर्युक्त टिप्पणियों का पहले ही निपटारा कर दिया गया है कि उत्पादक/ निर्यातक जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान किसी उत्पाद श्रेणी का निर्यात नहीं किया है, नई शिप्पर समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है।
- vi. घरेलू उद्योग ने इस बात पर बल दिया है कि यदि अलग अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण नई शिप्पर के लिए किया जाता है तब मूल जांच में नमूने न लिए गए उत्पादक/ निर्यातक के लिए उचित नहीं होगा। इस प्रकार से, मूल जांच में जब नमूने लेने की पद्धति अपनाई जाती है तब नई शिप्पर को पाटन के अलग अलग मार्जिन मंजूर नहीं किए जाने चाहिए।
- vii. सबसे पहले, घरेलू उद्योग नियम 17 के दूसरे परंतुक को नोट करने में असफल रहा है जिसमें नमूने न लिए गए उत्पादकों जो आवश्यक सूचना प्रस्तुत करते हों, के लिए पाटन के अलग अलग मार्जिन के निर्धारण का प्रावधान है। इस प्रकार से जब निर्दिष्ट प्राधिकारी पर उसी जांच में जिसमें नमूने लेने के लिए पद्धति अपनाई जाती है, उत्पादक अथवा निर्यातक के लिए पाटन के अलग मार्जिन के लिए अनुरोध पर विचार करने का है, एक नई शिप्पर समीक्षा में किसी नए निर्यातक को इस प्रकार के अधिकार से वंचित करने का कोई तर्क नहीं हो सकता है। इस प्रकार से नई शिप्पर की तुलना में नमूने न लिए गए उत्पादक को कोई हानि नहीं होती है।
- viii. दूसरा, नियम 17 में उत्पादन/ निर्यातक के लिए पाटन के अलग अलग मार्जिन के निर्धारण का प्रावधान है। हालांकि, यदि निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों अथवा शामिल वस्तु के प्रकारों की संख्या बहुत अधिक हो, तब प्राधिकारी को यह अनुमति दी जाती है कि वे अपने जांच परिणाम को हितबद्ध पक्षकारों के एक नमूने तक सीमित करें। दूसरी ओर, नई शिप्पर समीक्षा जिसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत किया जाता है, में नई शिप्पर के लिए पाटन के अलग अलग मार्जिन के निर्धारण का प्रावधान है। नियम 17 के विपरीत,

इसमें नमूने लेने की पद्धति को अपनाने का प्रावधान नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव देता हो कि नियम 17 के परंतुक को नियम 22 के ऊपर आरोप कर दिया जाना चाहिए।

- ix. तीसरा, प्राधिकारी की निर्यातकों के लिए पाटन के अलग अलग मार्जिन का निर्धारण करने के लिए नियम 22 की व्याख्या करने की सतत् प्रथा डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार के अंतर्गत इसके दायित्वों के अनुरूप है।
- x. चौथा, मूल जांच में नमूने न लिए गए उत्पादक/ निर्यातक को नई शिप्पर के समतुल्य रखना सही नहीं है। नमूने न लिए गए निर्यातक के विपरीत, जांच की मूल अवधि के दौरान नई शिप्पर में निर्यात नहीं किया और इसके पास नियम 17 के अनुसार अलग अलग जांच के लिए चयनित होने का कोई अवसर नहीं था।
- xi. अंत में, यह स्पष्ट नहीं है कि क्यों घरेलू उद्योग नमूने न लिए गए निर्यातक की ओर से हानि का दावा कर रहा है।
- xii. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया था कि वर्तमान जांच में प्रत्येक आवेदक के लिए नई शिप्पर समीक्षाओं को आरंभ करना अधिकारी के लिए जटिल है। हालांकि, घरेलू उद्योग इसके बारे में निर्णय नहीं ले सकता है कि एक से अधिक निर्यातक के लिए नई शिप्पर समीक्षा आयोजित करना प्राधिकारी के लिए बोझिल होगा। यह अधिकारी पर है कि वे इस संबंध में निर्णय करें कि क्या बोझिल है। इसके अलावा, पाटनरोधी नियमावली का नियम 22 और पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 9.5 इस आधार पर नई शिप्पर समीक्षा संबंधी अनुरोध को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं देता है कि नई शिप्पर समीक्षा की मांग करने वाले अनेक संभावित निर्यातक हैं। वास्तव में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन. गण. और यू. ए. ई. से विकटरी फाइड/ प्रोसिलेन टाइलों के आयातों के संबंध में करीब आठ नई शिप्पर समीक्षा जांच आयोजित की है। इस प्रकार से, और अधिक नई शिप्पर समीक्षा आवेदन प्राप्त होने की आशंका नई शिप्पर समीक्षा आवेदन को अस्वीकार करने के लिए आधार नहीं हो सकता है और यह निश्चित रूप से उस समीक्षा को समाप्त करने के लिए आधार नहीं हो सकता है जो पहले ही आरंभ की गई है। अंत में यह नोट किया जाता है कि नई शिप्पर समीक्षा को इस आधार पर अस्वीकार करना कि यह बोझिल है अथवा वह किन्हीं अन्य कारणों से उपयुक्त नहीं है जिसका स्पष्ट रूप से प्रावधान पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 में नहीं किया गया है, अनुच्छेद 9.5 के अंतर्गत दायित्वों से मेल नहीं खाते हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि इस आधार पर कि यह बोझिल है, नई शिप्पर समीक्षा अस्वीकार नहीं की जा सकती है।
- xiii. घरेलू उद्योग का यह दावा है कि यदि वर्तमान पाटन मार्जिन की तुलना में लागू पाटनरोधी शुल्क अधिक है, तब मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की मध्य अवधि समीक्षा के लिए निर्यातक अनुरोध कर सकते हैं। यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है जो अवधि समय तक चलने वाली हो, तब मध्य अवधि समीक्षा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत आरंभ की जाती है। प्रतिवादी द्वारा वर्तमान मामले में परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में कोई दावा नहीं किया गया।
- xiv. नई शिप्पर के लिए न्यूनतम पाटन मार्जिन को पहले ही अस्वीकार करना अनुमति योग्य नहीं है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.8 और पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(ग) में यह प्रावधान है कि जहां प्राधिकारियों ने यह निर्धारण किया कि पाटन का मार्जिन दो प्रतिशत अर्थात् न्यूनतम से कम हो, तब इन मामलों को तत्काल समाप्त नहीं किया जायेगा। यदि नई शिप्पर समीक्षा के अनुसरण में नए निर्यातक के लिए कोई अलग अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं हुआ हो, तब अनुच्छेद 5.8 को लागू करने के लिए कोई अवसर नहीं होगा। ऐसी कोई व्याख्या जो पूर्व के समग्र प्रावधान के लागू करने को दरकिनार करता हो, को नहीं अपनाया जा सकता है। यह भी संदेह नहीं किया जा सकता है कि अनुच्छेद 5.8 (और उसके माध्यम से पाटनरोधी नियमावली का नियम 41(ग)) नई शिप्पर समीक्षा के मामले में लागू नहीं है। कनाडा-वेलडेड पाइप ने पैनल की यह टिप्पणी थी कि :  
*हम ऐसा प्रतीत होता है कि एक स्पष्ट कारण है कि क्यों अनुच्छेद 5.8 के संबंधित भाग इस संदर्भ में अर्थात् यह सुनिश्चित करने के लिए लागू हो सकते हैं कि पाटन के न्यूनतम मार्जिन के साथ नए शिप्पर उसी प्रकार से पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन नहीं हैं, जिस प्रकार से मूल जांच में निर्यातकों की जांच की गई है।*
- xv. नियम 22 (2) में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार नई शिप्पर की समीक्षा से लंबित रहने के दौरान नई शिप्पर द्वारा किए गए निर्यातक के लिए अनंतिम आकलन का सहारा ले सकते हैं। एन एस आर जांच दिनांक 1 जनवरी, 2018 के आरंभन संबंधी अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी जूट सेकिंग बैग के आयात पर विशेष रूप से आरंभ किया गया था। जांच आरंभन संबंधी अधिसूचना का संगत पैरा नीचे दिया गया है।

“वर्तमान जांच इस अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन के मामले में विशेष रूप से जूट सेकिंग बैग के मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि. (उत्पादक और निर्यातक) द्वारा पाटन उत्पादों से प्रस्तावित निर्यात से संबंधित है।” (और अधिक बल दिया गया है)

xvi. हालांकि, पैरा 3 में जांच आरंभ संबंधी सूचना में, प्राधिकारी ने त्रुटिवश यह नोट किया कि :

**“प्राधिकारी मैसर्स जूट जनता जूट मिल्स लिमि. द्वारा किए गए संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर अनंतिम आकलन** इस समीक्षा के पूरा होने तक पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार और सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 01/2017 – सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 5 जनवरी, 2017 और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 11/2017 – सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 3 अप्रैल, 2017 के संबंध में सिफारिश करते हैं।” (और अधिक बल दिया गया)

xvii. वित्त मंत्रालय ने दिनांक 30 मई, 2018 के सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 30/2018 – सीमा शुल्क (ए डी डी) के माध्यम से “जूट उत्पादों” के अनंतिम आकलन को अधिसूचित किया था और उससे जूट यार्न/ट्वाइन, हैसियन फेब्रिक और सेकिंग बैग शामिल किया गया है। दिनांक 30 मई, 2018 के सीमा शुल्क अधिसूचना का संगत उद्धरण नीचे दिया गया है :

“इस कारण से अब, सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के नियम 22 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट प्राधिकारी की उपरोक्त सिफारिश पर विचार करने के बाद एतद् द्वारा आदेश देते हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उक्त समीक्षा के परिणाम से लंबित रहने तक, संबद्ध वस्तुओं जब वे बंगलादेश अथवा नेपाल के मूल के हों अथवा वहां से निर्यात किए गए हों, का मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि. (उत्पादक) द्वारा भारत में आयात किया गया हो, समीक्षा के पूरा होने तक अनंतिम आकलन के अधीन होगी” (और अधिक बल दिया गया)

xviii. अनंतिम आकलन की सीमा शुल्क अधिसूचना जारी किए जाने के पूर्व, फेब्रिक के लिए शुल्क की शून्य दर और जनता जूट द्वारा निर्यात किए गए जूट यार्न/ट्वाइन पर हैसियन और 20.6 यू. एस./मी. ट. लागू थे। हालांकि, सीमा शुल्क प्राधिकारी को अब जनता जूट द्वारा निर्यात किए गए इन वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम आकलन की आवश्यकता हो रही है और वे जूट यार्न और ट्वाइन के निर्यात के लिए बाण्ड और बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का अनुरोध कर रहे हैं।

xix. पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में उन वस्तुओं के अनंतिम आकलन की आवश्यकता है जिसके संबंध में नई शिप्पर समीक्षा आरंभ की गई है और न की किसी अन्य उत्पादों के लिए जिन पर किसी नई शिप्पर समीक्षा आरंभ की गई है।

xx. जनता जूट द्वारा जूट यार्न/ट्वाइन और हैसियन फेब्रिक के लिए गए निर्यातों के लिए अनंतिम आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क इन दो उत्पादों के निर्यात पर पहले से लागू है और जनता जूट द्वारा किए गए निर्यातों के लिए इन दो उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क की कोई नई शिप्पर समीक्षा नहीं की जा रही है। बैंक गारंटी का आग्रह आयातकों पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल रहा है और इससे जूट यार्न/ट्वाइन और हैसियन फेब्रिक के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वास्तविक देयता के बारे में अनिश्चितता पैदा हो रही है। हम निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे इस तथ्य को स्पष्ट करें कि जनता जूट द्वारा सेकिंग बैग के निर्यात के लिए नई शिप्पर समीक्षा आरंभ की जाये और इस कारण से पाटनरोधी नियमावली के नियम 22(2) के अनुसार सेकिंग बैग के आयात के लिए ही और न कि अन्य जूट उत्पादों अर्थात् एवं जूट यार्न/ट्वाइन के आयात के लिए अनंतिम आकलन की सिफारिश की जाये।

xxi. यह तथ्य कि सादत जूट इंडस्ट्री लिमि. प्रतिवादी का संबंधित प्रतिष्ठान है और यह कि बंगलादेश में प्रतिवादी का कोई अन्य संबंधित प्रतिष्ठान नहीं है कि भी स्पष्ट रूप से प्रतिवादी द्वारा मूल जांच में अनुरोध किया गया था। प्रतिवादी ने नई शिप्पर समीक्षा का अनुरोध करते हुए आवेदन में बंगलादेश में अपने संबंधित प्रतिष्ठान के संबंध में पूर्ण सूचना भी उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन में, प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित का उल्लेख किया है :

*“सादत जूट इंडस्ट्री लिमि. आवेदक का संबंधित प्रतिष्ठान है। सादत जूट इंडस्ट्री सेकिंग बैग का निर्माण नहीं करता है। यह केवल जूट यार्न/ट्वाइन का निर्माण करता है। आवेदक बंगलादेश अथवा नेपाल में कोई अन्य निर्यातक अथवा उत्पादक जो पाटनरोधी शुल्क के अधीन हों, से संबंधित नहीं है।”*



- xxii. अधिकतम अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्रतिवादी ने दिनांक 28 फरवरी, 2018 की व्यापार सूचना के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नये प्रपत्र के अनुसार निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर तो दायर किया ही। उत्पादन की प्रक्रिया, प्रमुख शेयर होल्डरों की सूची, भारत में विचाराधीन उत्पाद के बिक्री का मार्ग जैसी सभी संबंधित सूचना प्रतिवादी द्वारा प्रश्नावली के उत्तर के भाग के रूप में उपलब्ध कराई गई हैं।
- xxiii. घरेलू उद्योग का यह दावा है कि जांच के बाद की अवधि पर एक नई शिप्पर समीक्षा में पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे नई शिप्पर/ निर्यातक द्वारा मोल भाव किए जाने की संभावना उत्पन्न होती है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की प्रतिवादी ने वास्तविक बिक्री की है और इसमें कोई मोल भाव नहीं किया गया है, प्राधिकारी नई शिप्पर समीक्षा के आरंभ किए जाने की तिथि से पूर्व अर्थात् 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 के दौरान जनता जूट द्वारा निर्यात किए गए सेकिंग बैग की निर्यात कीमत की तुलना नई शिप्पर समीक्षा के आरंभ किए जाने की तिथि के बाद अर्थात् 1 जनवरी, 2018 से 30 जून, 2018 तक जनता जूट द्वारा निर्यात किए गए सेकिंग बैग की निर्यात कीमत से की जा सकती है। हम यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत टाइट मामले से लिये गए उद्धरण का संदर्भ माननीय सेसटेट की टिप्पणी से है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा *एच और आर जॉनसन (इण्डिया) लिमि. बनाम संघ सरकार* एवं अन्य (2008 (232) ई. एल. टी. 390) में चर्चा की गई थी। उच्च न्यायालय ने घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत उसी पैरा को नहीं माना और यह नोट किया कि पहली बार शिप्पर के मामले में पीछे की अवधि को नहीं लिया जा सकता है। इसके आधार पर उच्च न्यायालय इस पर सहमत हुआ कि नई शिप्पर समीक्षा के मामले में, जांच के बाद की अवधि की अनुमति अवश्य दी जानी चाहिए और उसे इन्कार नहीं किया जा सकता है।
- xxiv. घरेलू उद्योग का यह दावा है कि प्रतिवादी ने जांच प्रारंभ किये जाने से पूर्व अपने निर्यातों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है। घरेलू उद्योग नई शिप्पर की समीक्षा आरंभ करने के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर विचार करता है। वर्तमान जांच 1 जनवरी, 2018 को अर्थात् दिनांक 25 अप्रैल, 2018 के व्यापार नोटिस संख्या 08/2018 के माध्यम से नई शिप्पर को आरंभ करने का अनुरोध करने के लिए दायर किए जाने वाले नई शिप्पर से संबंधित आवेदन के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र के पूर्व आरंभ की गई थी। व्यापार सूचना जारी किए जाने से पूर्व, प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार की नई शिप्पर समीक्षा आरंभ करने के लिए अनुरोध करने हेतु आवेदन का कोई प्रपत्र निर्धारित नहीं किया गया था। इस प्रकार से यह दावा करना कानूनी रूप से सही नहीं है कि प्रतिवादी ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।
- xxv. घरेलू उद्योग प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वे प्रशासनिक सुविधा के लिए सभी मौजूदा नई शिप्पर समीक्षा को एक साथ मिला दें। घरेलू उद्योग इस प्रकार के अनुरोध के लिए कोई कानूनी आधार उपलब्ध नहीं कराता है। प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे यदि नियम 22 के अंतर्गत अपेक्षित शर्तों को पूरा कर लिया जाता है तब अलग अलग नए शिप्परों के लिए पाटन के अलग अलग मार्जिन का निर्धारण करें। इसके अलावा, अलग अलग तिथियों को छः नई शिप्पर समीक्षाएं पहले ही आरंभ की गई हैं और वे वर्तमान में जांच के विभिन्न चरणों में हैं। प्रत्येक नई शिप्पर समीक्षा के लिए जांच की अवधि और उत्पाद की श्रेणी अलग अलग है। इन समीक्षाओं में उत्पन्न होने वाले वास्तविक मुद्दे भी अलग अलग होंगे। इसके अलावा, यद्यपि इस समीक्षा को पूरा करने के लिए नियमावली के अंतर्गत कोई विशिष्ट समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, यह आशा की जाती है कि समीक्षा समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाए। पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 9.5 जिसमें नई शिप्पर समीक्षा का प्रावधान है, में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि नई शिप्पर समीक्षा को बढ़ाये गए आधार पर पूरा किया जाना चाहिए।
- xxvi. घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि नए निर्यातकों की अलग निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन वास्तविक रूप से अलग अलग नहीं हो सकती है और इस कारण से नई शिप्पर समीक्षा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अनुमान प्रारंभिक है और इसका कोई वास्तविक आधार नहीं है। किसी भी मामले में यदि निर्यात कीमत वास्तविक रूप से अलग अलग नहीं हो तब ये निर्यातक समीक्षा के अनुसरण में उसी अथवा समान पाटनरोधी दर के अध्वधीन होगी। इससे घरेलू उद्योग के हित को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी।
- xxvii. घरेलू उद्योग यह अनुरोध करने के लिए यूरोपीय यूनियन के कानून पर विश्वास करता है कि यदि मूल जांच में नमूने लेने की प्रक्रिया पूरी की गई है तब नई शिप्पर को अलग अलग पाटन मार्जिन के बजाय नमूने न लिये गये सहयोगी दलों को अवश्य मंजूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह भी दावा किया गया है कि

उन कीमतों जिन पर भारत में अलग अलग क्रेताओं ने बंगलोदश में अलग अलग आपूर्तिकर्ताओं से इन वस्तुओं की खरीद की है (आवश्यक रूप से निर्यात कीमत) वास्तविक रूप से अलग अलग नहीं हो सकता है और इस कारण से नमूने न लिये गए सहयोगी दर को लागू किया जाना चाहिए। यह नोट किया जाता है कि यूरोपीय संघ के कानून को फिर से घरेलू उद्योग द्वारा पेश किया गया है और यह अनुरोध है कि यूरोपीय संघ के कानून में निहित प्रावधान के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि वह पाटनरोधी अधिनियम में निहित कानून से आगे पहुंच गया है। किसी भी मामले में ऐसी प्रतिबद्धताएं वैश्विक रूप से लागू नहीं हैं और भारतीय पाटनरोधी नियमावली तथा अधिनियम में उसका कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार से निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह संभव नहीं है कि वे भारतीय कानून की स्पष्ट अभिदेश को देखते हुए यूरोपीय संघ के कानून के ऐसे प्रावधानों को शामिल करें।

- xxviii. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि प्रतिवादी ने यह अनुरोध करने के लिए *मैक्सिको में - बीफ और चावल* पर निश्चयात्मक पाटनरोधी उपाय के मामले में डब्ल्यू टी ओ के फैसले पर गलत तरीके से विश्वास किया है कि सहयोगी नमूने न लिये गये निर्यातक के लिए पाटनरोधी शुल्क की दर नये निर्यातक को नहीं दी जा सकती है। घरेलू उद्योग ने यूरोपीय यूनियन के कानून में दिए गए प्रावधान पर भरोसा किया है और प्राधिकारी से यह अनुरोध किया है कि वे उसी प्रथा का पालन करें। इस संबंध में हमारा यह अनुरोध है कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.4 में नमूने न लिये गये निर्यातकों के लिए पाटनरोधी शुल्क के निर्धारण का प्रावधान है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 में नई शिप्पर के लिए शुल्क के निर्धारण का प्रावधान है। इस प्रकार से नमूने न लिये गये निर्यातकों के लिए और नई शिप्पर के लिए पाटनरोधी शुल्क को स्थापित करने वाले प्रावधान हैं और उन दोनों प्रावधानों को एक साथ मिलाना और उन्हें उस तरीके से पढ़ना जो दोनों प्रावधानों को पढ़ते हों, के लिए कोई तर्क आधार नहीं है। एक नए निर्यातक जिसके लिए पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 के अनुसार किया जाना है, को अनुच्छेद 9.4 के अनुसार नमूने न लिये गये सहयोगी निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटनरोधी शुल्क दर को लागू करने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। अनुच्छेद 9.5 में अनुच्छेद 9.4 के प्रावधानों को नहीं लिया गया है और यह संदर्भ के द्वारा उसको शामिल नहीं करता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 9.5 में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप कटौती होती हो कि अनुच्छेद 9.4 के प्रावधान को अनुच्छेद 9.5 के उद्देश्य से लिया जा सकता है।
- xxix. यह अनुरोध किया जाता है कि यद्यपि *मैक्सिको - बीफ और चावल पर निश्चयात्मक पाटनरोधी उपाय* विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों से उत्पन्न हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि पैनल और अपीलीय निकाय की रिपोर्ट नई शिप्पर समीक्षाओं को नमूने संबंधी प्रावधान के लागू होने के कानूनी मुद्दे के संबंध में अंतिम है। हम दोहराते हैं कि अनुच्छेद 9.5 से अनुच्छेद 9.4 (नमूने लेना) में क्रॉस संदर्भ न होने की स्थिति में, अनुच्छेद 9.5 के अंतर्गत यथा निहित कानूनी प्रावधानों और उसके फलस्वरूप पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 की कोई व्याख्या अथवा विस्तृत पाटन नहीं हो सकता है।
- xxx. घरेलू उद्योग का यह दावा है कि जापन और संस्था के अंतर नियमों, स्वामित्व का विवरण, विचाराधीन उत्पाद, उत्पादन किए गए उत्पादों और निर्यात किए गए उत्पादों के निर्यात से संबंधित निर्यात दस्तावेज, संबंधित पक्षकारों के नाम और सूचना जैसे अनेक सूचनाएं दी गई हैं। हमारा अनुरोध है कि इस प्रकार के दावे का कोई आधार नहीं है और प्रतिवादी ने इस मामले में अपनी पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे दस्तावेज जिनके लिए गोपनीय के दावे किए गए हैं सार्वजनिक क्षेत्र के दस्तावेज नहीं हैं और इसमें व्यापार से संबंधित गोपनीय सूचना निहित है। दिनांक 25 मार्च, 2009 की व्यापार सूचना 1/2009 के अनुसार, प्रतिवादी से यह अपेक्षित था कि वे गोपनीय और अगोपनीय पाठों की अलग अलग प्रतियां प्रस्तुत करें, ऐसा किया गया है। दोनों के पाठों के बीच अंतर के आधार पर प्राधिकारी सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के लिए उस अनुरोध को स्वीकार कर सकते हैं अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। इस अनुरोध किया जाता है कि कुछ दस्तावेज जैसे प्रतिवादी का जापन और संस्था के अंतर नियम का सारांश नहीं किया गया था और इस दस्तावेज के शीर्षक दस्तावेजों की प्रकृति/ विषय वस्तु को समझने के लिए पर्याप्त हैं। एक अगोपनीय सार उपलब्ध कराने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्तर देने वाले पक्षकार उसका उत्तर देने में सक्षम हो सकें और ऐसे दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले किसी करार का मुकाबला कर सकें। हालांकि, वर्तमान परिदृश्य में इन दस्तावेजों को प्रतिवादी की प्रमाणिकता और इसके कानूनी अस्तित्व के संबंध में और न कि उठाये गये किसी कानूनी तर्कों के समर्थन में निर्दिष्ट प्राधिकारी की सूचना के लिए उपलब्ध कराया गया है।
- xxxi. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा की जा रही प्रवंचनारोधी जांच को देखते हुए सेकिंग कपड़ों की प्रतिवादी की बिक्री के संबंध में अतिरिक्त सूचना की मांग की है। इस संबंध में यह अनुरोध है कि नई शिप्पर समीक्षा

और प्रवंचनारोधी जांच का उद्देश्य और लक्ष्य पूर्ण रूप से अलग अलग है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि दो जांचों के अंतर्गत जांच किए गए उत्पाद भी पूर्ण रूप से अलग अलग हैं। इन दोनों जांचों को किसी भी रूप में एक साथ मिलाने के लिए कोई तर्काधार नहीं है।

- XXXii. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि प्राधिकारी द्वारा आयोजित सुनवाई "प्रभावी" नहीं है क्योंकि संबंधित सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई है और उसे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि नियम 22 में शामिल किए गए मानदंडों के संबंध में सभी संगत साक्ष्य प्राधिकारी को मौखिक सुनवाई से पूर्व उनके अगोपनीय पाठों के साथ साथ दी गई है। ऐसे सभी दस्तावेज सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध रहे। इस कारण से घरेलू उद्योग का दावा केवल कथन है और इस पर विचार किये जाने में कोई दम नहीं है। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे इस प्रकार के कथनों को अस्वीकार कर दें।
- XXXiii. घरेलू उद्योग का यह दावा है कि आयातकों से उत्तर प्राप्त न होना इस बात का साक्ष्य है कि प्रतिवादी ने किसी प्रकार से इस तथ्य को दबाने का प्रयास किया है कि निम्न अथवा कोई भी पाटन मार्जिन पर यह प्राप्त करने के उद्देश्य से अवास्तविक कीमत पर मामूली निर्यात किया गया था और उसके बाद आक्रामक रूप से मात्राओं का पाटन किया गया। हम नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने सिद्धांतों को रिकार्ड किया है और इस पैरा में कोई कानूनी अथवा तथ्यात्मक अनुरोध नहीं किए हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि न तो प्रतिवादी और न ही प्राधिकारी अपने आप किसी स्वतंत्र आयातक को किसी चालू जांच में भाग लेने के बाध्य कर सकते हैं। इस कारण से इस प्रकार की भागीदारी का न होना किसी भी चीज का साक्ष्य नहीं हो सकता है। घरेलू उद्योग का अनुरोध मात्र आरोप लगाने के लिए कथन और सिद्धांत है जिसका कोई कानूनी अथवा वास्तविक आधार नहीं है। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे इस प्रकार के कथनों को अस्वीकार कर दें।
- XXXiv. घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों को दोहराया है कि प्रतिवादी द्वारा निर्यातों की कम मात्रा यह दर्शाती है कि ये लेन देन किसी भी प्रकार से वास्तविक नहीं हैं। इस प्रकार के दावों में कोई दम नहीं है। प्रतिवादी फिर से यह कहते हैं कि नई शिप्पर समीक्षाओं के लिए लागू एक मात्र मापदंड नियम 22 में निहित है। "प्रतिवादी" अथवा "पर्याप्त" निर्यात के संबंध में अतिरिक्त मानदंडों को पढ़कर नियम 22 का विस्तार करने के प्रयास कानूनी नहीं हैं और इसका पहले ही निर्धारण उस प्रकार से होने के लिए डब्ल्यू टी ओ के पैनल और मैक्सिको में अपीलनीय निकाय - बीफ एवं चावल पर निश्चयात्मक पाटनरोधी उपाय में किया जा चुका है।
- XXXV. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से एक अन्य सुनवाई स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया है। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों के स्पष्ट न होने, अपने आप को प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अंतिम जांच परिणामों में यथा दर्ज किए गए मूल जांच की तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत कराये जाने में असफल होने और वर्तमान जांच को भ्रमित करने के लिए इसके प्रयासों को नोट करें। हम अनुरोध करते हैं कि घरेलू उद्योग इसमें प्रतिवादी द्वारा दिए गए दस्तावेजों को नोट करने में असफल रहे और जो प्राधिकारी द्वारा आयोजित सुनवाई के पूर्व सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराये गये थे और अब यह दावा कर रहे हैं कि यह सुनवाई प्रभावी नहीं थी क्योंकि इसमें संबंधित सूचना प्राप्त नहीं की जा सकी।

11. **आयातक/ प्रयोक्ता (मैसर्स चिरंजीलाल गौरी शंकर एंड कं. एंड उन्नति ओवरसीज) द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं :**

**- यह नोट किया जाता है वैसा ही अनुरोध मैसर्स गोल्डन फ्लोर फर्निशिंग प्रा. लिमि. (आयातक/ प्रयोक्ता) द्वारा किए गए हैं**

- i. यह अनुरोध किया जाता है कि मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि. ने जांच की अवधि के दौरान पाटनरोधी जांच में भाग लिया है और सहयोग किया है। जांच की अवधि के दौरान (1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक) मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि. ने भारत में जूट यार्न/ ट्वाइन और हैसियन फेब्रिक का केवल निर्यात किया था। प्राधिकारी ने अलग अलग पाटन मार्जिन का मूल्यांकन किया है और मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि. द्वारा निर्यात किए गए जूट यार्न/ ट्वाइन (20.68 यू. एस. डालर/ मी. ट.) और हैसियन फेब्रिक (शून्य शुल्क) पर पाटनरोधी शुल्क की अलग अलग दर की सिफारिश की थी। चूंकि मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि. ने जांच की अवधि के दौरान जूट सेकिंग बैग का निर्यात नहीं किया अतः भारत में जनता जूट मिल्स लिमि. द्वारा जूट सेकिंग बैग के निर्यात पर पाटनरोधी शुल्क की शेष दर (138.97 यू. एस. डालर/ मी. ट.) लागू की गई थी।

- ii. मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि. ने जूट सेकिंग बैग के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत एक नई शिप्पर समीक्षा के लिए आवेदन किया। एन एस आर जांच दिनांक 1 जनवरी, 2018 की अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जूट सेकिंग बैग के आयात पर विशेष रूप से आरंभ की गई थी।
- iii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में उन वस्तुओं के अनंतिम आकलन की आवश्यकता है जिसके संबंध में एन एस आर आरंभ की गई है और न कि किसी अन्य उत्पादों जिन पर कोई एन एस आर आरंभ नहीं किया गया है। तदनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जांच आरंभ संबंधी अधिसूचना ने नई शिप्पर समीक्षा के पूरा होने तक जनता जूट मिल्स लिमि. किए गए जूट सेकिंग बैग के निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क के अनंतिम आकलन की सिफारिश की।
- iv. इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि अनंतिम आकलन मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि. से सेकिंग बैग के आयातों के लिए ही अपेक्षित थी जिसके लिए एन एस आर आरंभ की गई थी और जारी है। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 30 मई, 2018 के सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 30/2018 – सीमा शुल्क (ए डी डी) के माध्यम जूट यार्न/ ट्वाइन, हैसियन फेब्रिक और सेकिंग बैग सहित “जूट उत्पादों” के अनंतिम आकलन को अधिसूचित किया था।
- v. यह अनुरोध किया जाता है कि वित्त मंत्रालय ने संबद्ध वस्तुओं अर्थात् सभी तीन जूट उत्पादों नामतः जूट यार्न/ ट्वाइन, हैसियन फेब्रिक और सेकिंग बैग पर भूलवश अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी। सीमा शुल्क के प्राधिकारी अब मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि. से जूट यार्न/ ट्वाइन और हैसियन फेब्रिक के आयातों पर आयातकों से एक बॉण्ड/ बैंक गारंटी का अनुरोध कर रहे हैं। जनता जूट मिल्स लिमि. द्वारा किए गए जूट यार्न/ ट्वाइन और हैसियन फेब्रिक के निर्यातों के लिए अनंतिम आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क पहले से ही लागू हैं और मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि. द्वारा किए गए निर्यातों के लिए इन जूट उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क की कोई एन एस आर नहीं चल रही है। बैंक गारंटी का आग्रह करने से आयातकों पर एक कठिन बोझ बढ़ रहा है और इससे जूट यार्न/ ट्वाइन और हैसियन फेब्रिक के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वास्तविक देयता के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न हो रही है।

#### **ड. प्राधिकारी द्वारा जांच**

12. पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में नीचे दिए गए अनुसार प्रावधान है :

*“निर्यातकों के लिए पाटन का मार्जिन जिसके लिए मूल रूप से जांच नहीं की गई।*

- (1) *यदि कोई उत्पाद पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन है तब निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रश्नगत निर्यात देश के किसी निर्यातकों अथवा उत्पादकों जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत में इस उत्पाद का निर्यात नहीं किया है के लिए पाटन के अलग अलग मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य से एक आवधिक समीक्षा करेगा बशर्ते कि ये निर्यातक अथवा उत्पादक यह दर्शाते हों कि वे निर्यातक देश जो इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन हैं, में इसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं हैं।*
- (2) *केंद्र सरकार इस नियमावली के उपनियम (1) में यथा संदर्भित समीक्षा की अवधि के दौरान इस प्रकार के निर्यातकों अथवा उत्पादकों से आयातों पर इस अधिनियम की धारा 9(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क नहीं लगायेगा :*

*बशर्ते कि यदि प्राधिकारी इस प्रकार से सिफारिश करते हैं और यदि इस प्रकार की समीक्षा के फलस्वरूप इस प्रकार के उत्पादों अथवा निर्यातकों के संबंध में पाटन का निर्धारण होता हो, केंद्र सरकार अनंतिम आकलन का सहारा ले सकती है और आयातक से गारंटी की मांग कर सकती है, यह समीक्षा के आरंभ होने की तिथि से ऐसे मामलों में स्पष्टगामी प्रभाव से शुल्क लगा सकती है।”*

13. डब्ल्यू टी ओ के करार के अनुच्छेद 9.5 में नीचे दिए गए अनुसार उल्लेख किया गया है -

*“यदि कोई उत्पाद किसी आयातक देश में पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन हों तब प्राधिकारी तत्परता से प्रश्नगत निर्यातक देश के किसी निर्यातकों अथवा उत्पादकों जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान आयातक देश को उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, के लिए पाटन के अलग अलग मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य से समीक्षा करेगा बशर्ते कि यह निर्यातक अथवा उत्पादक ये दर्शा सकें कि वे निर्यातक देश जो इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन हैं, में किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं हैं। इस प्रकार की समीक्षा आयातक देश में सामान्य शुल्क के आकलन और समीक्षा की कार्यवाहियों की तुलना में बंधे हुए आधार पर आरंभ की जायेगी और पूरी की जायेगी। कोई पाटनरोधी शुल्क समीक्षा किए जाने के समय इस प्रकार के निर्यातकों अथवा उत्पादकों से आयातों पर नहीं लगाया जायेगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारी मूल्यांकन को रोक सकते हैं और/ अथवा गारंटी का अनुरोध*

कर सकते हैं कि यदि इस प्रकार की समीक्षा के फलस्वरूप इस प्रकार के उत्पादकों अथवा निर्यातकों के संबंध में पाटन का निर्धारण होता हो, पाटनरोधी शुल्क इस समीक्षा के आरंभ होने की तिथि के पूर्व के समय से लगाया जा सकता है।

14. उपरोक्त नियम, डब्ल्यू टी ओ के करार के प्रावधानों और डी जी टी आर के विगत तथा के संबंध में, एक नई शिप्पर समीक्षा जांच संबद्ध देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क लगता है, के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक के संबंध में अलग अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य से निम्नलिखित परिस्थितियों किया जाना है :
  - i. यह कि निर्यातक अथवा उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है और
  - ii. निर्यातक अथवा उत्पादक यह दर्शाते हैं कि वे निर्यातक देश के किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक जो संबंधित उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अध्याधीन हैं, से संबंधित नहीं हैं।
15. वर्तमान मामले में मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि. ने जूट सेकिंग बैग पर अलग अलग पाटन मार्जिन की मांग करते हुए प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया और नई शिप्पर समीक्षा आरंभ करने के लिए अनुरोध किया।
16. 'एन एस आर' का दावा करने के लिए उत्पादक/ निर्यातक की पात्रता के संबंध में, प्राधिकारी ने मूल जांचों में उत्पादक/ निर्यातक द्वारा दायर किए गए आंकड़ों/ सूचना के संबंध में उत्पादक/ निर्यातक द्वारा किए गए दावे का संबंध बताया है। किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने किसी ठोस साक्ष्य के रूप में एन एस आर के लिए उत्पादक/ निर्यातक द्वारा शर्त को पूरा न किए जाने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। इस कारण से प्राधिकारी का यह मानते हैं कि उत्पादक/ निर्यातक वर्तमान मामले में एक नई शिप्पर समीक्षा की मांग करने के लिए पात्र है।

### **जांच का क्षेत्र**

17. प्राधिकारी मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद में शामिल किए गए सभी तीन प्रकारों पर नियम 22 की प्रयोजता की व्याख्या करते हुए क्षेत्र के निर्माण के संबंध में आयातकों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि एन एस आर से समीक्षा के अंतर्गत उत्पाद का क्षेत्र केवल जूट सेकिंग बैग है जैसा कि दिनांक 1.1.2018 के जांच आरंभन संबंधी अधिसूचना के पैरा 1 में उल्लेख किया गया है। अन्य दो उत्पाद प्रकारों अर्थात् जूट यार्न/ ट्वाइन (अनेक बार फोल्ड किया हुआ/ केबलड किया हुआ और एकल) और हैसियन फेबरिक जिसे मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद में शामिल किया गया है, इस समीक्षा का भाग नहीं है और इस कारण से इन दोनों प्रकारों पर लागू पाटनरोधी शुल्क वही होगा जिसका उल्लेख दिनांक 3 अप्रैल, 2017 के सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 11/2017 – सीमा शुल्क (ए डी डी) में क्रम संख्या 9 और 10 पर दिया गया है।

### **पाटन मार्जिन का निर्धारण और पाटनरोधी उपाय**

#### **सामान्य मूल्य**

18. उत्पादक/ निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन की लागत (सी ओ पी) दी है। प्राधिकारी ने 5 प्रतिशत लाभ को जोड़ने के बाद एक्स-फैक्ट्री सी ओ पी का निर्धारण \*\*\*टका/ मी. ट. के रूप में किया है, सामान्य मूल्य टका/ मी. ट. (\*\*\*)डालर/ मी. ट.) होता है।

#### **एक्स फैक्ट्री निर्यात कीमत**

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक/ निर्यातक ने सी आई एफ पर जांच की अवधि के दौरान 82655.66 टका/ मी. ट. का \*\*\* मी. ट. निर्यात किया है। अंतर्देशीय भाड़े, पोर्ट प्रभार और बैंक प्रभार पर भारत में निर्यात के लिए क्रमशः \*\*\*टका \*\*\* टका और \*\*\* अमरीकी डालर पर समायोजन पर विचार करने के बाद एक्स – निर्यात कीमत एकमात्र लेन देन के लिए \*\*\* टका/ मी. ट. (\*\*\*) डालर/ मी. ट.) होता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक्स निर्यात कीमत के लिए समायोजन के रूप में दावा किए गए निर्यात सब्सिडी स्वीकार्य नहीं है जैसा कि अनुच्छेद 2.4 के अंतर्गत पहचान किए गए समायोजनों में से एक समायोजन नहीं होने के कारण दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 के अंतिम जांच परिणाम के पैरा 127 (v) में मूल जांच परिणाम में भी माना गया था। हालांकि, इस निर्यात कीमत की उपयुक्तता पर विचार नीचे किया गया है।
20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक/ निर्यातक ने भारत में केवल \*\*\* मी. ट. मात्रा की 9.2.2017 को सेकिंग बैग का केवल एक लेन देन (निर्यात) किया है। मूल जांच में, अलग अलग पाटन मार्जिन के लिए विचार किए गए 2 नमूने लिए गए उत्पादक/ निर्यातक ने बहुत अधिक मात्रा अर्थात् अलग अलग 800 मी. ट. से अधिक का निर्यात किया था। नमूने न लिए गए उत्पादकों/ निर्यातकों जिन्होंने सहयोग किया था, को 2 नमूने लिए गए उत्पादकों/ निर्यातकों की औसत पाटन मार्जिन पर पाटन मार्जिन की स्वीकृति दी गई थी। भारत में सेकिंग बैग की वार्षिक मांग लगभग

50000 मी. ट. तक है और इस कारण से यह सिद्ध होता है कि कम मात्रा की खेप की कीमत प्रतिकात्मक है और इसके लिए उपयुक्त विश्लेषण की आवश्यकता है।

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चुनी गई जांच की अवधि के दौरान एक नए शिप्पर के द्वारा किए जाने वाले निर्यातों की मात्रा पर कोई शर्त नहीं है। हालांकि, जांच की अवधि के लिए प्रतिकात्मक होने के लिए निर्यात कीमत हेतु, निर्यात की मात्रा और फैलाव ऐसा होना चाहिए कि यह निर्यात कीमत की प्रतिकात्मकता, उपयुक्तता और विश्वसनीयता सुनिश्चित कर सके। नियम 22 में एक नये शिप्पर के लिए अलग अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने का प्रावधान है। चुनी गई जांच की अवधि ऐतिहासिक और बाद की अवधि दोनों हो सकती है क्योंकि जांच की अवधि के विकल्प के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में कोई प्रतिबंध नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने दिनांक 27.8.2007 के माननीय सेसटेट के आदेश का संज्ञान लेते हुए दिनांक 14.5.2008 आदेश के माध्यम से एच एंड आर जॉनसन (इण्डिया) लिमिटेड में बाद की अवधि के रूप में जांच की अवधि के संबंध में स्पष्ट किया है। वर्तमान मामले में विचार की गई जांच की अवधि ऐतिहासिक और बाद की अवधि दोनों हैं और वह भी पर्याप्त समय अवधि के लिए है, ताकि उत्पादक/ निर्यातक को एक उचित और तर्कसंगत अवसर दिया जा सके। उत्पादक/ निर्यातक जांच की अवधि की जांच आरंभ करने के बाद की अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक/ निर्यातक ने राजस्व विभाग द्वारा नियम 22 के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिसूचना से जारी किए जाने में विलंब के संबंध में अनुरोध किया है लेकिन निर्यातों पर किसी ठोस प्रतिबद्धता की कमी होने के संबंध में किसी ब्यौरे का उल्लेख उत्पादक/ निर्यातक द्वारा नहीं किया गया है। विगत निर्यात की प्रवृत्ति और निर्यातों के लिए जांच आरंभ के बाद की अवधि का लाभ नहीं उठाना यह दर्शाता है कि उत्पादक/ निर्यातक भारतीय बाजार में गंभीरतापूर्वक रुचि नहीं लेते हैं।
22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक/ निर्यातक ऐतिहासिक अवधि के दौरान केवल एक लेन देन का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने निर्यात कीमत की प्रतिकात्मकता को सिद्ध करने के उद्देश्य से अन्य आयातकों द्वारा उसी माह के दौरान सेकिंग बैग का लेन देन और बंगलादेश के जांच की अवधि के दौरान सेकिंग बैग की औसत मासिक आयात कीमत की भी जांच की है। दोनों मोर्चे पर तुलना यह दर्शाती है कि सेकिंग बैग के प्रकारों के लिए भी और निर्यात कीमतों में कुछ समय के दौरान बहुत अधिक अंतर है चूंकि सामान्य मूल्य का निर्धारण समग्र जांच की अवधि अर्थात् 18 महीने की अवधि के लिए उत्पादन की लागत के आधार पर, एक ओर 18 महीने का औसत सामान्य की तुलना करने पर पाटन मार्जिन की गणना के आधार पर किया गया है और एकमात्र आयात के लेन देन के साथ यह तर्कसंगत और उचित नहीं है।
23. अतः निर्यातों की एक सीमित मात्रा का एकमात्र लेन देन के साथ, प्राधिकारी उत्पादक/ निर्यातक को इस आंकड़े के आधार पर विशिष्ट पाटन मार्जिन देने के लिए इसे उपयुक्त नहीं मानते हैं।
24. हालांकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक/ निर्यातक ने इसके बावजूद निर्यात करने का इरादा दर्शाया है और लघु मात्रा में निर्यात भी किया है और इस कारण से प्राधिकारी तदनुसार शेष श्रेणी के उपाय की तुलना में आवेदक उत्पादक/ निर्यातक के नमूने न लिए गए श्रेणी पर लागू पाटनरोधी उपाय को पर विचार करते हैं।
25. प्राधिकारी एन एस आर में आवेदक उत्पादक/ निर्यातक को नमूने न लिए गए उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए लागू किए गए उपाय की मात्रा देने में उपयुक्तता के संबंध में घरेलू उद्योग और उत्पादक/ निर्यातक दोनों के अनुरोध को नोट करते हैं। प्राधिकारी यह समझते हैं कि एन एस आर आवेदक को संभव सीमा तक एन एस आर के जांच के दौरान उनके वास्तविक निर्यातों के आधार पर अलग अलग पाटन मार्जिन दिए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, इसका मूल्यांकन करने के लिए, उत्पादक/ निर्यातक को उस मात्रा का निर्यात करने की आवश्यकता है जो व्यापारिक मात्रा हो सकती है जिससे यह सिद्ध करना सुनिश्चित हो सके कि निर्यात कीमत विश्वसनीय है और उस पर किसी प्रकार का धब्बा नहीं लगा है। केवल कुछ सांकेतिक निर्यात करना अधिकारी को निर्यात कीमत की विश्वसनीयता को सिद्ध करने में सक्षम नहीं बनाता है। प्राधिकारी इस अनुरोध को समझते हैं कि अगर उत्पादक/ निर्यातक में मूल में निर्यात किया होता तब वह नमूने लिए गए श्रेणी में होन का विकल्प ले सकता था और यह कि वही अवसर उन्हें एन एस आर जांच में भी दिए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऐसे उत्पादक/ निर्यातक को पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत एक अवसर दिया जाता है जिसका आवेदक उत्पादक/ निर्यातक द्वारा किसी औचित्यपूर्ण दावे को सिद्ध करने के लिए उसी रूप में गंभीरतापूर्वक लाभ उठाये जाने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तब उस स्थिति में नमूने न लिये गये उत्पादकों/ निर्यातकों जो नमूने लिये गए उत्पादकों/ निर्यातकों का औसत है पर लागू पाटनरोधी उपाय किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं होता यदि उसे आवेदक उत्पादक/ निर्यातक पर लागू किया होता। यह समझने की जरूरत है कि नमूने न लिए उत्पादक/ निर्यातक भी या तो उपरोक्त औसत स्तर से अधिक अथवा उससे कम हो सकते हैं। इस कारण से वर्तमान मामले में आवेदन उत्पादक/ निर्यातक के लिए, नमूने न लिए गए उसी श्रेणी का उपाय उपयुक्त और औचित्यपूर्ण है।

**च. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां**

26. घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हुए मैसर्स टी पी एम ने निम्नलिखित प्रकटन पश्चात टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं

- (i) एक निर्यातक अलग शुल्क के लिए तभी पात्र होगा यदि इसमें यह दर्शा कर अपने दायित्व का प्रभावी रूप से निर्वहन किया हो कि नियम 22 के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा कर दिया गया है। यह अनुरोध किया जाता है कि यह निर्यातक आवेदक है जिन्हें यह दर्शाना है कि एन एस आर और न कि घरेलू उद्योग के लिए अनिवार्य शर्तों को पूरा कर लिया गया है। आवेदन, लिखित अनुरोध और जारी किए गए प्रकटन विवरण में भी ऐसा कुछ नहीं है जो यह दर्शाता हो कि इन अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है। नई शिप्पर समीक्षा के रूप में पात्रता को दर्शाते हुए दस्तावेज निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक नए शिप्पर के रूप में एक निर्यातक पर विचार करने के लिए अपेक्षित है। इसे दर्शाये जाने की आवश्यकता है कि पर्याप्त बिक्री एक उपयुक्त निर्यात कीमत सिद्ध करने के लिए किया गया है।
- (ii) घरेलू उद्योग ने लिखित अनुरोध में इस तथ्य का विस्तार से उल्लेख किया है कि आवेदक एक बेइमान निर्यातक है। वर्तमान जांचों में, स्वीकार्य रूप से आवेदक 'सादत जूट इंडस्ट्री लिमि.' नामक एक संबंधित प्रतिष्ठान है। हालांकि यह दावा किया गया है उक्त उत्पादक जूट सेकिंग बैग का उत्पादन नहीं करता है, यह केवल जूट यार्न का उत्पादन करता है और इसीलिए इसने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। यह नोट करना यहां संगत है कि आवेदक ने मूल जांच में अपने संबंधित पक्षकार के संबंध में तथ्यों को प्रकट नहीं किया। इसके अलावा, निर्यातक की प्रश्नावली 'सादत जूट इंडस्ट्री लिमि. जो जनता जूट मिल्स लिमि., मूल जांच में उत्तर देने वाले निर्यातक की एक संबंधित कंपनी है और वर्तमान जांच में आवेदक है, को भेजी गयी थी। हालांकि, जूट यार्न/ ट्वाइन के उत्पादक/ निर्यातक होने के बावजूद जैसा कि वर्तमान जांच के लिए आवेदन में दावा किया गया है, 'सादत' ने इसे पूर्व की जांच में प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए संगत नहीं माना। इस तथ्य को छोड़कर की प्रश्नावली उत्तर प्राप्त करने के लिए भेजी गयी थी परंतु उसका जवाब नहीं दिया गया था, मूल जांच में 'सादत' का कोई उल्लेख नहीं है। वर्तमान आवेदन में यह उल्लेख है कि 'सादत' जूट यार्न/ ट्वाइन के निर्माण में लगा हुआ है। हालांकि, घरेलू उद्योग इसे आश्चर्यजनक पाता है कि क्यों उक्त संबंधित पक्षकार ने मूल जांच में प्रश्नावली का उत्तर करने से परहेज किया जब यह मूल जांच के समय भी विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगा हुआ था। इसका अर्थ यह है कि पूर्ण उत्तर न दिए जाने की स्थिति में, मूल जांच में प्रश्नावली का उत्तर अपने आप में पूरा नहीं था और आवेदक को अलग शुल्क प्राप्त करना पड़ा। मौखिक सुनवाई के समय यह दावा किया गया था कि आवेदक ने मूल जांच में यह उल्लेख किया था कि वे एक संबंधित पक्षकार हैं जिन्होंने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है। यह तथ्य के आधार पर सही नहीं है और यह कथन गुमराह करने वाला है। आवेदक को इस कथन को सिद्ध करने के लिए कहा जा सकता है। प्रश्नावली के उत्तर के अगोपनीय पाठ के संगत पृष्ठ को लिखित अनुरोधों के साथ पूर्व में संलग्न किया गया था। यह देखा जायेगा कि निर्यातक ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया था कि इसका कोई ऐसा संबंधित अथवा सहायक कंपनी नहीं है जो विचाराधीन उत्पाद में शामिल है। उपयुक्त सूचना मैसर्स सादत जूट इंडस्ट्री लिमि. द्वारा दी जानी चाहिए थी।
- (iii) यह अनुरोध किया जाता है कि न्यूनतम अनिवार्य सूचना जिसकी 25 अप्रैल, 2018 को प्राधिकारी द्वारा जारी की गई एन एस आर जांच के लिए नई प्रश्नावली में अपेक्षित है, निम्नलिखित है :

- क. जांच की अवधि के दौरान आपके बिक्री के खाते की प्रति
- ख. जांच की अवधि के बाद प्रति देश मासिक बिक्री की सूची
- ग. संस्था के अंतर नियम/ संस्था का ज्ञापन
- घ. पंजीकरण प्रमाण पत्र
- ङ. जांच की अवधि के दौरान कंपनी के प्रमुख शेयर होल्डरों की सूची
- च. सदस्यता प्रमाण पत्र (व्यापार संघ आदि)
- छ. यदि लागू हो तो निर्यात अनुज्ञा पत्र
- ज. यदि लागू हो उत्पादन अनुज्ञ पत्र
- झ. भारत में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री का मार्ग
- ञ. विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन की प्रक्रिया

- ट. विचाराधीन उत्पाद के लिए संयंत्र की संस्थापित क्षमता के समर्थन में साक्ष्य
- ठ. विचारधीन उत्पादन के लिए डीजल बनाने की प्रक्रिया
- ड. ब्रोशर और सामान्य कंपनी दस्तावेजीकरण
- ढ. जांच की अवधि के बाद और जांच की अवधि के पूर्व किये गये निर्यात के लिए भारत में निर्यात दस्तावेजों के दो सेट
- ण. भारत में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री रद्द न किए जाने वाली संविदागत करारों का साक्ष्य
- त. विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के उद्देश्य से उत्पादन उपकरण की नमूना खरीद डीजल
- थ. विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के उद्देश्य से उपयोग की गई कच्चे माल का नमूना खरीद डीजल
- (iv) यह तथ्य कि प्राधिकारी ने पूर्व में कोई विशिष्ट निर्धारण नहीं किया और अब आवेदन के लिए विशिष्ट निर्धारण किया है, का अर्थ यह नहीं होता है कि इस प्रकार की सूचना वर्तमान जांच के लिए आवश्यक नहीं है। इसका अर्थ केवल यह होता है कि - (क) यह सूचना याचिका के चरण में ही अपेक्षित थी; (ख) अपेक्षाओं की सूची में बहुत विशिष्ट दस्तावेज हैं जिन्हें पात्रता को सिद्ध करने के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए और (ग) वे दस्तावेज जिनमें प्राधिकारी द्वारा पात्रता को सिद्ध करने के लिए अपेक्षित है। इस प्रकार से हितवद्ध पक्षकार केवल इस कारण से इस अपेक्षा से नहीं बच सकते हैं कि इसे बाद में सूची में जोड़ा गया है। यह प्रपत्र केवल स्पष्ट करने की प्रकृति का है। यह प्रपत्र यह सिद्ध करता है कि जिस पर विचार किया गया है वह इस मामले को सिद्ध करने के उद्देश्य से संगत, उपयुक्त और आवश्यक है। इस प्रकार से अपर्याप्त सूचना और साक्ष्य आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
- (v) एन एस आर घरेलू उद्योग के लिए एक अंतर्निहित जोखिम पैदा करता है जिसमें पाटनरोधी शुल्क आदेश को लगाये जाने के माध्यम से अनुचित रूप से व्यापार किए गए आयातों से राहत प्राप्त की है जैसा कि अक्सर मामला होता है, एक निर्यातक अथवा उत्पादक एक अथवा कुछ उच्च कीमत बिक्री अथवा जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के निर्यात के आधार पर एक नई शिप्पर का अनुरोध करता है जो व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में कार्यरत किसी कंपनी के लिए वाणिज्यिक रूप से तर्कसंगत नहीं है। अन्य आयात कीमतों की तुलना में अत्यधिक "सभी अन्य" दर और नई शिप्पर की उच्च कीमत का समुच्चय का अभिप्राय दो बातें हो सकती हैं: या तो नये शिप्पर ने वास्तव में उच्च कीमत पर बिक्री की पुनरावृत्ति की है जिस पर इसने समीक्षा के पूर्व किया था अथवा नई शिप्पर औसत पाटन मार्जिन से कम मार्जिन प्राप्त करने के लिए एक उच्च कीमत बिक्री और उसके पश्चात प्रकार रूप से बहुत कम कीमत वसूलने (प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए बहुत कम कीमत पर जो अपेक्षाकृत अधिक पाटन मार्जिन होता है लेकिन फिर भी बहुत अधिक लाभ कमाता है जो अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं होता) का लाभ उठायेगा। यह देखे जाने की आवश्यकता है कि क्या विचाराधीन बिक्री विशेष की है और यह नई शिप्पर से भावी बिक्री का द्योतक होगा।
- (vi) यह दर्शाये जाने की आवश्यकता है कि जांच की अवधि के दौरान नई शिप्पर आवेदक द्वारा किए गए निर्यात इसके अपने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन दिए जाने के लिए पर्याप्त है। न केवल यह कि निर्यातक का इस उत्पाद में एक बार निर्यात लेन देन हुआ था जहां भारत में मांग 13,70,000 मी. ट. (वर्तमान मामले की जांच की अवधि के 18 महीने के लिए) के करीब है और भारत में बंगलादेश से कम से कम 322 जात निर्यात लेन देन हुए थे। यदि बंगलादेश के निर्यातक मूल जांच की जांच की अवधि के दौरान 43,626 मी. ट. उत्पाद का निर्यात करते और यदि उस उत्पाद प्रकार के लिए उस जांच की अवधि में 1,430 लेन देन हुआ होता, तब यह सामान्य नहीं है कि आवेदकों के पास केवल एक निर्यात लेन देन हुआ है। निर्दिष्ट प्राधिकारी से निर्यात लेन देन के आधार पर पाटन मार्जिन तय करने के लिए कहा जाता है। 'वास्तविक बिक्री' की अवधारणा नई शिप्पर समीक्षा के पी ओ आर के दौरान गलत लेन देन कर पाटनरोधी शुल्क से बचने के प्रयासों को रोकने के लिए आवश्यक है। उद्देश्य "व्यापार के उचित मूल्य की जांच करना नहीं है बल्कि उनके वाणिज्यिक तर्कसंगतता के लिए निर्यात की जांच करना है।"
- (vii) वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने पैरा 20 में यह अनुरोध किया है कि निर्यातक ने फरवरी 2017 में केवल एक बार लेन देन किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने यह भी टिप्पणी की है कि निर्यातक ने उसके बाद कोई निर्यात नहीं किया है और इस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि निर्यातक भारतीय बाजार के बारे में गंभीर नहीं हैं। प्राधिकारी ने विशेष रूप से नीचे दिए गए अनुसार नोट किया है :

अतः निर्यात की एक सीमित मात्रा की केवल एक लेन देन के साथ, प्राधिकारी उत्पादक/ निर्यातक को इन आंकड़ों के आधार एक विशिष्ट पाटन मार्जिन देने के लिए इसे उपयुक्त नहीं मानते हैं।



(viii) इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि भारत में आवेदकों द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा भारत में खपत की तुलना में बहुत ज्यादा कम है। निर्यातक को यह अवश्य ही दर्शाना चाहिए कि क्यों यह वर्तमान अवधि के दौरान अपेक्षाकृत अधिक मात्राओं का निर्यात करने में सक्षम नहीं था। संपूर्ण प्रयास को अत्यधिक रूप से प्रबंधित किया गया है। आवेदकों द्वारा किए गए लेन देन प्रतिकात्मक नहीं हैं, गलत इरादे से किए गए हैं और वे वाणिज्यिक रूप से तर्कसंगत नहीं हैं और यह इस तथ्य का पालन करता है कि उनके द्वारा दर्शायी गई निर्यात कीमत पर विचार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वे उस कीमत को नहीं दर्शाते हैं जिस पर आवेदक भविष्य में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करेगा। इस प्रकार की निर्यात कीमत औपचारिक निर्यात लेन देन से सिद्ध नहीं हो सकती है। इस प्रकार की निर्यात कीमत पर विचार भारत में कुल आयातों और इस देश में उत्पाद की खपत के संबंध में जुड़ी मात्राओं के साथ साथ की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में जहां 322 लेन देन को शामिल करते हुए 13,70,000 मी. ट. आयात किया गया था, कोई पक्षकार यह तर्क नहीं दे सकता है कि यह लागू पाटनरोधी के कारण बहुत अधिक मात्रा में निर्यात करने में सक्षम नहीं था। किसी भी मामले में, लागू पाटनरोधी शुल्क का मौजूद होना निर्यात करने में सक्षम नहीं हो पाने के लिए बहाना नहीं हो सकता है। वास्तव में कोई तर्क कि पक्षकार पाटनरोधी शुल्क के कारण निर्यात नहीं कर सका, इस बात का द्योतक है कि कानून पहले से ही यह मानता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के कारण संबंधित देश से निर्यात को पूर्ण रूप से वापिस ले लिया जायेगा। इस समीक्षा को इन आधारों पर समाप्त कर दिया जाना चाहिए कि उपयुक्त निर्यात कीमत तुलना के लिए उपलब्ध नहीं है और शेष शुल्क आवेदकों पर लागू किया जाना चाहिए।

(ix) घरेलू उद्योग ने आर-134क के आयातों के संबंध में एन एस आर जांच के मामले में हाल की जांच परिणामों का संदर्भ लिया जिसमें प्राधिकारी ने विशेष रूप से किए गए निर्यात की कम मात्रा के संबंध में नीचे दिए गए अनुसार नोट किया है।

*आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान तब भी चीन से आयातों की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री नहीं की है जब आवेदक को अनंतिम आकलन का हक प्राप्त था और अन्य उत्पादक/निर्यातक पाटनरोधी शुल्क के कारण हानि उठा रहे थे। उन्होंने बहुत कम मात्रा में निर्यात किया है जो अलग अलग निर्धारण का कोई आधार नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अलग अलग पाटन मार्जिन प्राप्त करने में समग्र प्रयास में निर्यात करने के लिए निर्यातक के पास गंभीरता का अभाव है।*

(x) विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। यह प्रकटन विवरण से स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग यह जान पाये कि आयातकों ने वर्तमान जांच में अनुरोध किए हैं। इसके अलावा इसमें तथ्य को दबाने के लिए जानबूझ कर किये गये प्रयासों का पता चलता है कि कम अथवा शून्य पाटन मार्जिन प्राप्त करने के उद्देश्य से और उसके बाद मात्राओं को आक्रामक रूप से पाटित करने के उद्देश्य से अवास्तविक कीमत पर सांकेतिक निर्यात किया गया था। आयातकों से प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने के मद्देनजर, निर्दिष्ट प्राधिकारी को आयात कीमत की उपयुक्तता की जांच करने से रोक दिया गया है। इस कारण से आयातक की प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिये जाने के कारण से ऐसा हुआ है कि आयात लेन देन सामान्य उच्च कीमत पर आधिकारिक रूप से की गई है और इस कारण से यदि आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करते हैं और उस कीमत को दर्शाते हैं जिस पर इन वस्तुओं का आयात किया गया था, के नहीं होने पर संपूर्ण मामले पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। यदि इन वस्तुओं का आयात व्यापार के उद्देश्य से किया गया होता तब आयातक को यह दर्शाना पड़ता कि इसने आयात कीमत पर विचार करते हुए लाभ लेकर सामग्री की बिक्री की है, यह किसी आयातक के लिए दर्शाना संभव नहीं है कि इसने लाभ लेकर उत्पाद की बिक्री की है। कोई भी आयातक बाजार में इस उत्पाद की खपत नहीं कर सकता था। आयातक बाजार केवल इस उत्पाद की बिक्री कर सकता था। केवल इसी कारण से कि प्राधिकारी को भ्रमित करने के लिए केवल एक निर्यात लेन देन हुआ है कि निर्यात कीमत है।

(xi) आयातों के आधार पर पाटन मार्जिन, अलग अलग शुल्क मंजूर करने का आशय सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को सही तरीके से सिद्ध करना है। इसके अलावा, निर्यात कीमत को सही तरीके से सिद्ध करने के लिए आयात कीमत की तर्कसंगतता को सिद्ध करना अपेक्षित होता है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्राधिकारी ने जांच के अवधि के रूप में विगत अवधि को मंजूर किया है और इस कारण से आवेदक पाटनरोधी शुल्क के कारण बहुत अधिक मात्रा में निर्यात करने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे मामले में जहां पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के बाद भी बहुत अधिक आयात हुआ है और निर्यातक को एक अनंतिम आकलन आदेश दिया गया था। मूल जांच के समय और जांच की वर्तमान अवधि के समय बंगलादेश से क्रमशः 3,636 मी. ट. और 543 मी. ट. के औसत आयात के बावजूद, आवेदक ने केवल 20 मी. ट. का औपचारिक निर्यात किया है। इस प्रकार से, किसी भी स्थिति में आवेदक ने यह सिद्ध नहीं किया है कि इसे इसके अपने पाटन मार्जिन के आधार पर

अलग अलग शुल्क दिया जाना चाहिए और नमूने लिये गये सहयोगी निर्यातकों जिनकी पूर्व में प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी, के आधार पर अलग अलग शुल्क को मंजूर करना उपयुक्त नहीं है।

- (xii) इसके बावजूद, घरेलू उद्योग इसका पुनः उल्लेख करते हैं आवेदक को मूल जांच में नमूने में शामिल न किए गए सहयोगी कंपनियों को दी गई औसत भारित शुल्क दिया जा सकता है क्योंकि मूल जांच में नमूने लेना शामिल था। इस संबंध में निम्नलिखित को नोट करना संगत है :

- क. आवेदक मूल मामले के नमूने न लिए गए सहयोगी उत्पादकों की तुलना में अधिक लाभकारी स्थिति की मांग नहीं कर सकते हैं। यदि सहयोगी नमूने न लिए गए उत्पादकों को अलग अलग शुल्क नहीं दिया जाता तब एन एस आर आवेदक अपने निजी आंकड़ों के आधार पर शुल्क पर आग्रह नहीं कर सकते हैं।
- ख. नियम 17 निर्यातकों को उनके अपने पाटन मार्जिन के लिए हक प्रदान करता है। परंतु यह अधिकार नमूने लेने संबंधी प्रावधानों द्वारा अधिक्रमित हो जाता है/ कम हो जाता है/ सीमित हो जाता है।
- ग. निर्दिष्ट प्राधिकारी पर भार नमूने लेने के लिए मौलिक औचित्य है और यह एन एस आर के लिए भी संगत रहेगा।
- घ. कोई भी तर्क की उनके अपने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर अलग अलग पाटन मार्जिन नहीं देने से बड़े हुए पाटन मार्जिन होगा और ये निर्यातक पाटनरोधी शुल्क की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे जैसा कि उस स्थिति में भुगतान के योग्य होता यदि उस प्राधिकारी उनके अपने आंकड़ों पर विचार किया होता, हमेशा सही नहीं हो सकता है। वास्तव में ऐसी स्थिति हो सकती है जहां निर्यातक के अपने आंकड़े नमूने न लिए गए सहयोगी निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन की तुलना में अधिक अथवा कम पाटन मार्जिन दर्शा सकते हैं।
- ङ. एन एस आर इस जांच को पाटन मार्जिन तक ही सीमित करता है। नमूने न लिये गये सहयोगी उत्पादकों पर मूल शुल्क क्षति मार्जिन पर भी हो सकता है। इस प्रकार से नमूने न लिये गये सहयोगी उत्पादकों को दिये गये शुल्क का विस्तार करने के फलस्वरूप प्रतियोगी हितबद्ध पक्षकारों के हितों में बहुत अधिक संतुलन भी होगा। इस प्रकार से सुविधा का संतुलन यह सुझाव देता है कि नमूने न लिये गये सहयोगी उत्पादकों को पूर्व में सिफारिश किये गये शुल्क जांचों के सभी पक्षकारों के लिए न्यायोचित निष्पक्ष होगा। किसी भी मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नमूने लेने से संबंधित कानून के आधार पर मूल जांच के समय नमूने न लिये गये सहयोगी उत्पादकों पर सिफारिश किया गया शुल्क गैर कानूनी है क्योंकि यह वास्तविक पाटन मार्जिन से अधिक होता है अथवा कम होता है। वास्तव में नमूने न लिये गये सहयोगी उत्पादकों पर शुल्क पाटन मार्जिन का आकलन किये बिना भी लगाया जाता है।
- च. एक ऐसी स्थिति जहां निर्यातक को इसके अपने पाटन मार्जिन की तुलना में अधिक शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, का निराकरण समीक्षा कानूनों में किया गया है। इस प्रकार से केवल यह तथ्य कि नमूने न लिये गये सहयोगी उत्पादकों की श्रेणी में अथवा एन एस आर में एक पक्षकार को पाटन मार्जिन की तुलना में अधिक शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है, का पूरी तरह से समाधान कानून के अंतर्गत किया गया है। वास्तव में लगान के समय एक पक्षकार को वास्तविक पाटन मार्जिन की तुलना में अधिक अथवा कम शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि इसका समाधान समीक्षा प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है।
- छ. मूल जांच में आयातों की मात्रा और उत्पाद कवरेज जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए नमूने के बारे में निर्णय लिया गया था। इस कारण से मूल जांच के समय निर्धारित पाटन मार्जिन वैज्ञानिक रूप से निकाले गये नमूने के आधार पर होता है।
- ज. आवेदक द्वारा किये गये निर्यातों की मात्रा आमतौर पर जूट उत्पादों के विभिन्न प्रकारों और विशेष तौर पर सेकिंग बैग के आयातों की कुल मात्रा की तुलना में बहुत कम है। जबकि मूल जांच के समय तब भी नमूने लेना उपयुक्त था जब मात्रा बहुत कम थी, एन एस आर के मामले में जहां जांच की अवधि आंशिक रूप से पश्चगामी और आंशिक रूप से आगे की अवधि हो पर, तब आवेदक द्वारा निर्यातों की कम मात्रा निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है।

- झ. चूंकि निर्यात कीमत वह कीमत है जिस पर इन वस्तुओं का निर्यात भारतीय बाजार में खपत के लिए किया गया है, वह कीमत जिस पर भारत में अलग अलग क्रेताओं ने संबद्ध देश से अलग अलग आपूर्तिकर्ताओं से वस्तुओं की खरीद की है वास्तविक रूप से अलग अलग नहीं हो सकती है। संबद्ध देश के भौगोलिक रूप से नजदीक होने पर विचार करते हुए बंगलादेश में अलग अलग उत्पादकों द्वारा खर्चों में बहुत अधिक अंतर नहीं हो सकता है। हालांकि, जांच में यह दर्शाया है कि मासिक आधार पर तथा उस महीने जिसमें आवेदक निर्यातक इन वस्तुओं का निर्यात किया अर्थात् फरवरी 2017 के लिए लेन देन वार आधार पर सभी निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमतों के संबंध में बहुत अधिक अंतर रहा है।
- ञ. यूरोपीय संघ की यह प्रथा भी है कि वह एन एस आर के नमूने न लिये गये सहयोगी उत्पादकों को मंजूर करे तथा उक्त प्रथा को कानूनी न्यायालय अथवा डब्ल्यू टी ओ द्वारा गैर कानूनी या अनुप्रयुक्त भी नहीं पाया गया है। जबकि यह यूरोपीय यूनियन की प्रथा है अतः डब्ल्यू टी ओ करार के अंतर्गत पद्धति की अनुमेयता के संबंध में स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन कर रहा है।

27. उत्पादक/ निर्यातक का प्रतिनिधित्व करते हुए मैसर्स एल के एस ने प्रकटन पश्चात निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं :

- (i) प्राधिकारी ने प्रतिवादी की निर्यात कीमत को अस्वीकार कर दिया है और इसने प्रतिवादी के लिए पाटन की अलग अलग मार्जिन का निर्धारण नहीं किया है। प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय का समर्थन करने के लिए दिया गया एकमात्र कारण यह है कि प्रतिवादी ने जांच की अवधि के दौरान एक बार निर्यात लेन देन के माध्यम से सेकिंग बैग का सीमित मात्रा में निर्यात किया है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि प्रतिवादी को नमूने न लिये गये उत्पादक/ निर्यातक पर लागू पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करना उचित है।

***i पाटन का अलग अलग मार्जिन के निर्धारण के लिए एक नई शिप्पर समीक्षा में निर्यात की वाणिज्यिक मात्रा पर जोर देना पाटनरोधी कराकर के अनुच्छेद 9.5 और पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के प्रतिकूल है।***

- (ii) इस संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि उसी महीने में सेकिंग बैग की आयात कीमत में परिवर्तन का प्रतिवादी के निर्यात कीमत की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेकिंग बैग की कीमत सिलाई के आकार/ वजन/ प्रकार और फेवरिक को बुनने में आ रही दिक्कतों पर निर्भर करता है। इस प्रकार से यह आशा की जाती है कि विभिन्न निर्यातकों द्वारा बिक्री की कीमत अथवा अलग अलग आयातकों द्वारा खरीद की कीमत उसी अवधि के दौरान भी परिवर्तन दर्शायेगी।
- (iii) यह पूर्व शर्त की निर्यात वाणिज्यिक मात्रा में होना चाहिए और/ अथवा जांच की अवधि के दौरान होना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 के विपरीत है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में यह उल्लेख किया है कि प्राधिकारी यदि "(i) उत्पादक अथवा निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान भारत में उत्पाद का निर्यात नहीं किया है और (ii) यह उत्पादक या निर्यातक निर्यात करने वाले देश जो इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन हैं, में निर्यातकों अथवा उत्पादकों में से किसी से संबंधित नहीं हैं, की पाटन के अलग अलग मार्जिन का निर्धारण करने के लिए नई शिप्पर समीक्षा करेगा। नियम 22 के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित मानदंड पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत नई शिप्पर समीक्षाओं पर लागू एकमात्र मानदंड है।
- (iv) नियम 22 के अंतर्गत ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि नये शिप्पर द्वारा निर्यात कुछ न्यूनतम मात्रा का होना चाहिए और/ अथवा यह कि इस प्रकार के निर्यात अलग अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण की अनुमति देने के लिए एक विशेष समयावधि तक होनी चाहिए। ऐसी अपेक्षा करने के बाद प्राधिकारी ने "प्रतिकात्मक" अथवा "पर्याप्त" निर्यातों के नियम 22 के अंतर्गत अतिरिक्त मानदंड को जोड़ा है। अन्य शब्दों में निर्यात की "प्रतिकात्मकता" को आवश्यक बनाकर प्राधिकारी ने एक शर्त लगाई है जिसका प्रावधान नियम 22 में नहीं किया गया है।
- (v) **मैक्सिको – चावल में,** मैक्सिको के विदेश व्यापार अधिनियम (एफ टी ए) की धारा 89घ को चुनौती दी गई थी क्योंकि धारा 89घ में यह प्रावधान था कि नई शिप्पर समीक्षा के लिए अनुरोध करने वाले पक्षकार के निर्यात की मात्रा प्रतिकात्मक होनी चाहिए। अनुच्छेद 89घ मैक्सिकन जांच प्राधिकारी (इकोनोमिया) को एक त्वरित समीक्षा करने के लिए अनुमति देती थी बशर्ते कि अन्य बातों के साथ साथ प्रतिवादी निर्यातक समीक्षा की अवधि के दौरान मैक्सिको में निर्यात की 'प्रतिकात्मक' मात्रा दर्शाती हो, अपीलीय निकाय ने उसमें नोट किया कि ऐसा आवश्यक कर अनुच्छेद 89घ एक ऐसी शर्त लगाता है जो पाटनरोधी करार के

संगत प्रावधानों में नहीं दिया गया था। अतः अनुच्छेद 89घ इकोनोमिया को उन मामलों में समीक्षा की मंजूरी देने से रोकता है जहां संगत डब्ल्यू टी ओ प्रावधानों में दी गई शर्तों को वास्तव में प्रतिवादी<sup>1</sup> द्वारा पूरा कर लिया गया है। इसके फलस्वरूप, अपीलीय निकाय ने यह माना कि एफ टी ए की धारा 89घ “इस प्रकार से” अनुच्छेद 9.5 के अनुरूप नहीं है।

- (vi) इस प्रकार से यह मान लिया गया है कि प्राधिकारी उन शर्तों जिन्हें नियम 22 के अंतर्गत नहीं दिया गया है को जोड़कर अलग अलग पाटन मार्जिन प्राप्त करने से प्रतिवादी को नहीं रोक सकता है।

**ii नमूने न लिये गये निर्यातकों के लिए लागू पाटनरोधी शुल्क पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत एक नये शिप्पर पर लागू नहीं किया जा सकता है।**

- (vii) प्रकटन विवरण के पैरा 25 में, प्राधिकारी ने प्रतिवादी को नमूने न लिये गये एक उत्पादक/ निर्यातक के रूप में माना और इसने यह उचित माना है कि प्रतिवादी को नमूने न लिये गये उत्पादक/ निर्यातक के लिए पाटनरोधी शुल्क दर को लागू करे।
- (viii) पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 में निर्यातकों के लिए पाटन का अलग अलग मार्जिन का प्रावधान है बल्कि यह भी प्रावधान है कि यदि निर्यातकों की संख्या बहुत अधिक हो तब प्राधिकारी को अपने जांच परिणाम कुछ हितवद्ध पक्षकारों तक सीमित करने की अनुमति दी जाती है। दूसरी ओर, पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में नये शिप्पर के लिए पाटन के अलग अलग मार्जिन के निर्धारण का प्रावधान है। नियम 17 के ठीक विपरीत, नियम 22 में ऐसा कोई परंतुक नहीं है और इस कारण से किसी भी परिस्थिति में नमूने लेने से संबंधित पद्धति को अपनाने की अनुमति नहीं है। ऐसा सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि नियम 17 के नमूने लेने संबंधी परंतुक को नियम 22 पर ऊपर से डाल दिया जाना चाहिए।
- (ix) उसी प्रकार से, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.4 में नमूने न लिये गये निर्यातकों के लिए पाटनरोधी शुल्क के निर्धारण का प्रावधान है। दूसरी ओर, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 में नये शिप्पर के लिए शुल्क की अलग अलग दर के निर्धारण का प्रावधान है। अनुच्छेद 9.5 अनुच्छेद 9.4 का संदर्भ नहीं लेता है और अनुच्छेद 9.4 के नियम अनुच्छेद 9.5 पर लागू नहीं होते हैं। *मैक्सिको – चावल में*, पैनल की रिपोर्ट के पैरा 7.159 में पैनल ने नोट किया कि पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 9.4 जिसमें नमूने न लिये गये पाटनरोधी शुल्क पर दर का प्रावधान है, नई शिप्पर पर नहीं लागू होता है।
- (x) इस प्रकार से, मूल जांच में नये निर्यातक और नमूने न लिये गये निर्यातक उत्पादक एक समान नहीं हैं और उन्हें पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के उद्देश्य से तुलना नहीं की जा सकती है।

**iii रिकार्ड पर साक्ष्य यह सुझाव देता है कि प्रतिवादी भारतीय बाजार में रुचि रखते हैं और उन्होंने नई शिप्पर समीक्षा के अवसर का लाभ उठाया है।**

- (xi) प्राधिकारी ने गलत तरीके से यह टिप्पणी की है कि विगत निर्यातों की प्रवृत्ति और निर्यातों के लिए जांच आरंभ किये जाने की बाद की अवधि का लाभ नहीं उठाना यह दर्शाता है कि प्रतिवादी भारतीय बाजार में गंभीर रूप से रुचि नहीं रख रहे हैं। भारत में 28 नवंबर, 2015 से 14 दिसंबर, 2016 के बीच सेकिंग बैग की 384 मी. ट. का निर्यात प्रतिवादी ने किया।
- (xii) प्राधिकारी ने गलत तरीके से यह नोट किया है कि 23 मी. ट. का आयात सेकिंग बैग की 50,000 मी. ट. की मांग पर विचार करते हुए पर्याप्त नहीं है। मूल जांच की जांच की अवधि के दौरान 50,000 मी. ट. की मांग इस नई शिप्पर समीक्षा की जांच की अवधि के दौरान 23 मी. ट. के आयात से तुलना नहीं की जा सकती है। बाजार की सूचना के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस नई शिप्पर समीक्षा की जांच की अवधि अर्थात् 1 जनवरी, 2017 से 30 जून, 2018 के दौरान बंगलादेश से सेकिंग बैग का आयात बहुत कम मात्रा में हुआ था। इस प्रकार से, प्रतिवादी 23 मी. ट. का आयात इस अवधि के दौरान सेकिंग बैग के कुल आयातों की तुलना में बहुत कम मात्रा में नहीं हुआ है।
- (xiii) प्राधिकारी ने प्रतिवादी के अनुरोध को नोट किया है कि अनंतिम आकलन को आवश्यक बनाने वाले सीमा शुल्क अधिसूचना को जारी किये जाने में विलंब हुआ था। हालांकि, प्राधिकारी की यह टिप्पणी है कि निर्यात की किसी ठोस प्रतिबध्ता के नहीं होने के किसी ब्यौरे का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि ग्राहक ने 5 जनवरी, 2017 को पाटनरोधी शुल्क लगाये जाये जाने के बाद सेकिंग बैग के आदेश को रद्द किया है। इसके अलावा, प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि आयातक द्वारा सेकिंग बैग के दो खरीद

<sup>1</sup> अपीलीय निकाय की रिपोर्ट, मैक्सिको - चावल, पैरा 323-324

आदेश दिये गये थे जिन्हें बाद में पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के कारण रद्द कर दिया गया था। यह स्पष्ट है कि जैसे ही पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, प्रतिवादी सेकिंग बैग की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा का निर्यात करने के लिए भारत में अपने ग्राहकों से आदेश प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुआ था। जब नई शिप्पर समीक्षा 1 जनवरी, 2018 को आरंभ की गई थी, प्रतिवादी यह आशा कर रहे थे कि नियम 22 के अनुसार अनंतिम आकलन को आवश्यक बनाने वाली सीमा शुल्क अधिसूचना जारी हो जायेगी। हालांकि, अनंतिम आकलन को आवश्यक बनाने वाली सीमा शुल्क अधिसूचना को 30 मई, 2018 को ही जारी किया गया था। गंभीर उद्देश्य और इच्छा के बावजूद, प्रतिवादी भारत में सेकिंग बैग का निर्यात नहीं कर पाये थे क्योंकि 138.97 यू. एस. डालर/ मी. ट. का पाटनरोधी शुल्क नई शिप्पर समीक्षा के आरंभ किये जाने के बाद भी सेकिंग बैग के निर्यात पर निश्चित रूप से वसूला गया था।

- (xiv) वास्तव में प्रतिवादी की ओर से यह सही नहीं होगा कि वह सेकिंग बैग के निर्यात की मात्रा को अधिकतम करने के उद्देश्य से पाटनरोधी शुल्क को अवशोषित कर अनुचित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करे। प्रतिवादी अपने मानक प्रथा से विपथित नहीं हुआ और इसने तब भी जांच की अवधि के दौरान भारत में सेकिंग बैग का निर्यात किया जब यह बाजार की मांग के अनुसार उपयुक्त कीमत प्राप्त करने में सक्षम था।
- (xv) इसके अलावा, न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता को शुरू करना प्राधिकारी के मूल जांच में अपने निर्णय के विरुद्ध है। मूल जांच की जांच की अवधि में प्रतिवादी ने दो निर्यात लेन देन के द्वारा 6.99 मी. ट. हैसियन फेबरिक का निर्यात किया। इस तथ्य को प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम के पृष्ठ संख्या 45 पर भी नोट किया गया है। प्राधिकारी ने इन लेन देन के आधार पर हैसियन फेबरिक की प्रतिवादी की निर्यात कीमत को स्वीकार किया और शून्य पाटनरोधी शुल्क दर का निर्धारण किया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि 6.9 मी. ट. की निर्यात मात्रा पर प्राधिकारी द्वारा हैसियन फेबरिक के निर्यात के लिए प्रतिवादी द्वारा अलग अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से प्रतिकात्मक अथवा विश्वसनीय नहीं होने के कारण विचार नहीं किया गया था। इस प्रकार से नई शिप्पर समीक्षा में 23 मी. ट. सेकिंग बैग की उपयुक्तता का निर्धारण करते समय कोई अलग अलग मानक नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्यों प्राधिकारी ने इस नई शिप्पर समीक्षा में एक नये और अलग अलग मानदंड को स्वीकार किया है।
- (xvi) प्रतिवादी इस तथ्य को उजागर करना चाहते हैं कि इन्होंने जांच की पूरी प्रक्रिया के दौरान पूर्ण सहयोग किया है और प्राधिकारी द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार सभी आंकड़े और सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं। उसके अलावा 23 मी. ट. का निर्यात लेन देन नई शिप्पर समीक्षा आरंभ किये जाने के पूर्व हुआ था जो इस बात का साक्ष्य है कि निर्यात कीमत में किसी प्रकार का तोड़ मरोड़ नहीं किया गया है। प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराई गई निर्यात कीमत से संबंधित सूचना का विधिवत सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया गया था। इस प्रकार से प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराई गई निर्यात कीमत विश्वसनीय है और अपने आप में सूचना की सत्यता अथवा सटीकता के बारे में संदेह करने के लिए कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने वास्तविक बिक्री की है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत अवसर का गंभीरतापूर्वक लाभ उठाया है।
- (xvii) अंत में प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि स्वयं प्रतिवादी इस तथ्य को मानते हैं कि एक नई शिप्पर समीक्षा में आवेदक को अलग अलग पाटन मार्जिन दिये जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदक ने नियम 22 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा किया है। प्राधिकारी नियम 22 के अंतर्गत निर्धारित कानूनी आवश्यकताओं के अलावा और अधिक शर्तों को नहीं जोड़ सकते हैं। प्रतिवादी प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे अपने निर्णय पर फिर से विचार करें और पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार प्रतिवादी को पाटन के अलग अलग मार्जिन प्रदान करें।

#### छ. प्राधिकारी द्वारा जांच :

28. प्राधिकारी घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स टी पी एम और मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि. (उत्पादक/ निर्यातक) की ओर से मैसर्स एल के एस द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रकटन पश्चात टिप्पणियों को नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने जांच की अवधि के दौरान किये गये एन एस आर के लिए विचार किये जा रहे संबद्ध वस्तुओं अर्थात् सेकिंग बैग के निर्यातों की मात्रा के पर्याप्त होने से संबंधित अनुरोध किये हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स एल के एस ने यह उल्लेख किया है कि मूल जांच में भी केवल 8 मी. ट. हैसियन फेबरिक का निर्यात किया गया था और यह कि जांच की अवधि के दौरान समग्र आधार पर सेकिंग बैग के आयात बहुत कम हैं और यह कि उनके द्वारा सेकिंग बैग के निर्यात की 23 मी. ट. पर्याप्त है, इस समग्र संदर्भ में मैसर्स एल के एस ने आगे यह उल्लेख किया है कि नियम 22 के अंतर्गत एन एस आर में निर्यात की मात्रा की किसी न्यूनतम सीमा की कोई शर्त नहीं है।

29. उपर्युक्त अनुरोधों को नोट करते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि मूल जांच में जांच की प्रकृति और एन एस आर की तुलना दृष्टिकोण, विचार विमर्श की प्रकृति और किये गये विश्लेषण के पहलुओं पर नहीं की जा सकती है क्योंकि इन दो जांचों में चुनौतियां और बाधाएं बिलकुल अलग अलग हैं जबकि नियम 22 के अंतर्गत एन एस आर में जांच की अवधि के दौरान निर्यात की न्यूनतम मात्रा पर कोई न्यूनतम सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। अतः यह नहीं माना जा सकता है कि प्राधिकारी निर्यात कीमत की तर्कसंगतता और विश्वसनीयता को सिद्ध करने के लिए उपयुक्त विचार विमर्श और दृष्टिकोण लागू नहीं करेंगे। इसके प्रति एक अपेक्षा कुछ तर्कसंगत मात्रा की उपलब्धता और प्रतिकात्मकता के लिए जांच की अवधि के दौरान इसका तर्कसंगत फैलाव है। प्राधिकारी मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि. द्वारा निर्यात के महीने में सेकिंग बैग की कीमतों के परिवर्तन पर एल के एस के अनुरोध को नोट करते हैं और यह समझते हैं कि ऐसे किसी माह में बैग के आकार, प्रकार के कारण सेकिंग बैग की कीमतों में अंतर हो सकता है। हालांकि, प्रति मी. ट. आधार पर प्रवृत्त वाली सेकिंग बैग की कीमत कुल मिलाकर आकार के परिवर्तनों के समान है। अन्य प्रमुख मानदंड जिसका कीमत पर प्रभाव पड़ता हो, उपयोग किये गये यार्न का काउंट हो सकता है। सेकिंग बैग का उपयोग कुल मिलाकर पैकेजिंग उपयोगों के लिए है और इसलिए गुणवत्ता संबंधी अंतर के व्यापक होने की आशा नहीं है। वर्तमान मामले में निर्यात का एकमात्र लेन देन निश्चित रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्यात कीमत की विश्वसनीयता को सिद्ध करने के लिए सीमा रखती है।
30. प्राधिकारी ने 'एन एस आर' में इस बात पर बल दिया, कि निर्यातक को उनके द्वारा निर्यात के पश्चात सिफारिश किये जाने वाले उपाय पर निर्यात कीमत के प्रभाव के बारे में जानकारी है। प्राधिकारी के समक्ष यह सिद्ध करने की चुनौती है कि निर्यात कीमत को बाधित और प्रबंधित नहीं किया गया है बल्कि ये वास्तविक हैं। यदि विभिन्न ग्राहकों से विभिन्न ग्राहकों निर्यात की कीमत उपलब्ध होती है और वह जांच की अलग अलग अवधि में, अन्य निर्यातकों के अन्य समान लेन देन के साथ इन कीमतों की तुलना प्राधिकारी को निर्यात कीमतों की वास्तविकता और तर्कसंगतता सिद्ध करने में सक्षम बनाता है। इस कारण से वर्तमान मामले में, आवेदक उत्पादक/ निर्यातक का निर्यात व्यवहार प्राधिकारी को इस प्रकार का कार्य करने के लिए अवसर उपलब्ध नहीं कराता है।
31. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि नियम 22 के अंतर्गत दिनांक 30.05.2018 अधिकार प्रदान करने वाली सीमा शुल्क अधिसूचना में विलंब हुआ था फिर भी इस अधिसूचना के जारी किये जाने के बाद निर्यातक ने एकमात्र लेन देन में निर्यात नहीं किया। नियम 22 प्राधिकारी पर यह दायित्व डालता है कि वे केवल अलग अलग पाटन मार्जिन और न कि एल डी आर लागू करने के लिए क्षति की सदृश्य सीमा का निर्धारण करें।

### निष्कर्ष

32. अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, उत्पादक/ निर्यातक पर विचार मूल जांच में निर्यातकों की नमूने न लिये गये श्रेणी के लिए सिफारिश किये गये अनुसार पाटनरोधी उपाय के लिये किया जा सकता है। यह उपाय चूंकि कमतर शुल्क नियम के लागू होने पर आधारित है और इस कारण से दी गई परिस्थितियों में, उत्पादक/ निर्यातक पर इसकी प्रयोजता वास्तव में निष्पक्ष और उपयुक्त होगी। तदनुसार प्राधिकारी नीचे दिए गए अनुसार सिफारिश करते हैं :

### सिफारिश

33. (i) दिनांक 9.2.2017 अधिसूचना संख्या 14/19/2015 – डी जी ए डी (दिनांक 20.10.2016 के अधिसूचना संख्या 14/19/2015 – डी जी ए डी का शुद्धि पत्र) के पैरा 132 में उल्लिखित मौजूदा शुल्क तालिका में प्रविष्टि 47 को नीचे दिये अनुसार जोड़ा जाये :

क्र. सं.	शीर्षक/ उप शीर्षक	वस्तु का विवरण	बिनिर्देशन	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
47.	5307, 5310, 5607 और 6305	सेकिंग बैग	सभी रूपों और बिनिर्देशों में	बंगलादेश	बंगलादेश	जनता जूट मिल्स लिमि.	जनता जूट मिल्स लिमि.	125.21	यू. एस. डालर/ मी. ट.

- (ii) दिनांक 30.05.2018 के सी. एन. संख्या 30/2018 - सीमा शुल्क (ए डी डी) के अनुसार और न कि इस सीमा शुल्क अधिसूचना के अनुसार जांच की अवधि अर्थात् 1.1.2017 से 30.06.2018 के दौरान किये गये सेकिंग बैग

के निर्यात को उपर्युक्त (i) के अनुसार विनियमित किया जाये। आगे स्पष्ट करने के लिए मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि. द्वारा 1.1.2017 से किये गये सेकिंग बैग का निर्यात उपयुक्त (i) में यथा उल्लिखित पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन होगी जो दिनांक 3.4.2017 की सी. एन. 11/2017 – सीमा शुल्क (ए डी डी) के मौजूद रहने के समय तक लागू रहेगा।

- (iii) अन्य संबद्ध वस्तुओं अर्थात् जूट यार्न/ ट्वाइन (अनेक बार फोल्ड किया हुआ/ केबल किया हुआ और एकल), हैसियन फेब्रिक और जूट सेकिंग बैग और हैसियन फेब्रिक यदि उसका निर्यात मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि. द्वारा 1.1.2017 से 30.6.2018 के दौरान किया गया हो इस एन एस आर का हिस्सा नहीं है और इस कारण से वे और मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमि. द्वारा उनके भावी निर्यात दिनांक 3.4.2017 के सी. एन. संख्या 11/2017 – सीमा शुल्क (ए डी डी) द्वारा शासित होना जारी है।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2018

### FINAL FINDINGS

**Subject :** New Shipper Review under Rule 22 of Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 pertaining to Anti-Dumping Duty imposed on the imports of "Jute Products" viz – Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian Fabric and Jute Sacking Bags originating in or exported from Bangladesh, as requested by M/s Janata Jute Mills Ltd. (P), regarding Sacking Bags initiated on 1.1.2018.

**F. No. 7/10/2017- DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

#### **A. Background of the Case**

- Whereas, in the original Anti-Dumping investigation, the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) recommended, inter alia, imposition of anti-dumping duty on the imports of "Jute products" viz- Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabric, and Jute sacking bags, originating in or exported from Bangladesh and Nepal, falling under Chapter 69 of the Customs Tariff Act, 1975, vide Final findings Notification No. 14/19/2015-DGAD dated 20<sup>th</sup> October, 2016. The Central Government notified the definitive anti-dumping duty vide Notification No. 01/2017-Customs (ADD) -Customs dated 5<sup>th</sup> January 2017 and Customs Notification No. 11/2017-Cus (ADD) dated 3rd April, 2017.
- M/s. Janata Jute Mills Ltd. (Producer and Exporter) filed an application for New Shipper Review (NSR) in terms of Rule 22 of the Anti-dumping Rules read with the Customs Tariff Act, requesting for a New Shipper Review (NSR) claiming individual dumping margin in respect of imports of the sacking bags, originating in or exported from Bangladesh which was not exported by them during the POI of the original investigation wherein AD measure has been imposed vide Custom Notification no. 11/2017-Cus (ADD) dated 3rd April, 2017.
- The Authority, having been prima facie satisfied with the conditions laid down under Rule 22 of Anti-dumping Rules, initiated a New Shipper Review investigation, vide Notification No. 7/10/2017-DGAD

dated 1<sup>st</sup> January 2018, for determination of individual dumping margin for the purposes of imposition of the anti-dumping duties levied on the dumped imports of Jute Sacking Bags originating in or exported from Bangladesh, in respect of M/s. Janata Jute Mills Ltd. (Producer).

5. Ministry of Finance notified the provisional assessment on all exports of the subject goods made by M/s Janata Jute Mills Limited till completion of the aforesaid NSR investigation vide Notification No. 30/2018- Customs (ADD) dated 30<sup>th</sup> May, 2018.
6. The period of investigation for the purpose of this New Shipper Review was fixed as 1st January, 2017 to 30th June, 2018.

#### **B. PROCEDURE**

7. The procedure described below has been followed with regard to the present investigation:
  - (i) The Authority issued a public notice vide Notification No. 7/10/2017-DGAD dated 1<sup>st</sup> January 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject NSR anti-dumping investigation.
  - (ii) The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the applicant along with a copy of the exporter's questionnaire and gave them opportunity to make their views known in writing, and filing relevant data in the prescribed Questionnaire, after expiry of the POI.
  - (iii) The Authority also forwarded a copy of the initiation notification to the High Commission of Bangladesh in India.
  - (iv) The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the known domestic producers in India and gave them opportunity to make their views known in writing.
  - (v) In response to the initiation notification, Questionnaire response was filed by M/s. Janata Jute Mills Ltd., the applicant for NSR.
  - (vi) The Authority made available non-confidential version of submissions/ information filed by various interested parties, in the form of a public file, kept open for inspection by interested parties.
  - (vii) The Authority held an Oral Hearing on 6<sup>th</sup> September, 2018 to provide an opportunity to interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6) followed by written submissions. The interested parties were allowed to present rebuttal rejoinders on the views/information presented by other interested parties. The Authority has considered submissions received from various interested parties appropriately.
  - (viii) All relevant Submissions/comments made by interested parties, during the course of this investigation have been considered and included in this final finding.

#### **C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

8. The product under consideration in the original investigation is 'Jute Products' comprising of Jute yarn/twine (multiple folded/cabled and single), Hessian Fabrics and Jute Sacking bags. The Authority had recommended separate duty for each type of Jute products in the original investigation to producers. This investigation is pertaining to exports of Sacking Bags only i.e. one of the product types of the PUC considered in original investigation, as stated in the Para 1 of the initiation notification dated 1.1.2018.

#### **D. SUBMISSIONS BY VARIOUS INTERESTED PARTIES AND DOMESTIC INDUSTRY :**

9. **Submissions by the Domestic Industry:**
  - i. The applicant sought the present initiation without providing adequate and necessary information. The Petition lacks information and evidence to show that the applicant satisfies requirements of Rule 22. Applicant needs to establish that it is bonafide exporter who has made bonafide sales, has not exported goods in the original investigation and is not related to producer/exporter of subject goods attracting duty.



- ii. Applicant filed questionnaire response on 31<sup>st</sup> August 2018 while Authority formulated new questionnaire format for NSR investigation on 25<sup>th</sup> April. Despite taking sufficient time, questionnaire response filed does not meet the new format.
- iii. Applicant admitted ignorance on whether it exported to India during POI for original investigation which shows the petition does not contain any evidence that the applicant did not export PUC during the POI of the original investigations. The investigation has been initiated without meeting such important requirement under law.
- iv. Nothing in the application shows that the requirement to show that the applicant is not related to any exporter or producer in the exporting country who are subject to anti-dumping duties on the product is fulfilled. Such vital requirement of Rule 22 has not been met before seeking new shipper review investigation. The applicant has failed to provide any evidence in this regard.
- v. Authority chose a prospective period as period of investigation i.e., a period which includes subsequent period to the initiation of investigation under Rule 22. There were admittedly exports by the applicant in the past. Instead of considering those exports, the authority chose to proceed on the basis of a prospective POI, which is inappropriate. Applicant in such a case would have been able to manipulate and doctor the data by doing insignificant number of transactions at high prices during period of investigation. This concept has been criticized by the CESTAT in Tiles case.
- vi. In the past the authority has initiated new shipper review investigations only upon satisfaction of sales made or firm commitment made for exports. Evidences required under the law constitute of exports made after the POI and before the POI along with irrevocable contractual agreements for sales of the product to India. However, none of these have been given with the application.
- vii. Exports made by the applicant during the period of investigation must be bona fide commercial transactions to form basis for dumping margin. It has to be seen whether the sale under consideration is typical and will be representative of the new shipper's future sales. The genuineness of these sales, both in terms of value and volume, should be examined.
- viii. Concept of 'bona fide sale' in U.S.A. was introduced to counter attempts of avoidance of duty by undertaking mala fide transactions during POR. It was necessitated to ensure that transactions during POR were representative of "shipper's future commercial practice, and to ensure that the shipper is not attempting to circumvent the duty order". The purpose was to "examine each sale for its commercial reasonableness". This concept was codified in Section 433 of Trade Facilitation and Trade Enforcement Act Of 2015 where the vital factors are considered to determine bona fide sales.
- ix. Different NSR investigations initiated should be clubbed together as the requirement under law is to 'carry out a periodical review' implying that applications should be entertained at set or fixed intervals and not as and when the applications are filed. It would also be of administrative convenience to club these together.
- x. Applicant has not established its case for grant of individual dumping margin and in the absence of which it may be given weighted average duties given to the cooperating companies not included in the sample in the original investigation, since the original investigation involved sampling.
- xi. Under Rule 17, exporters are entitled to their own dumping margin but this right under Rule 17 gets superseded/ qualified by the further provision of sampling under Rule 17 which authorises the Authority not to determine individual dumping margin for each known exporter/ producer.
- xii. Determination of individual dumping margin only increases the burden on the authority and considering the product categories and number of producers there are about 855 possible combinations in which goods could have been exported to India. All these channels were not used in the POI of original investigations and therefore there is a high number of channels available for exports. Determining individual margins for each new shipper would be burdensome for the authority.
- xiii. Rule 22 provides for the phrase 'time to time' which simply implies at set intervals thereby indicating at bunching of the number of reviews initiated in the present investigation.
- xiv. The cooperating non-sampled producers cannot be at a disadvantage as compared to a new shipper as they were also not accorded individual margins.

- xv. Any argument that non granting of individual dumping margin based on their own normal value and export price might lead to exaggerated dumping margin and these exporters may be made to pay a higher quantum of ADD as would have been payable, had that authority considered their own data implies that the sampling law is illegal. A situation where exporter needs to pay a duty higher than its own dumping margin is addressed in review laws.
- xvi. No prejudice is caused to exporters if dumping margin is not determined based on their data and such exporters are subjected to ADD on the basis of ADD originally determined for sampled cooperating exporters.
- xvii. Authority has to consider and compare import volumes reported by responding exporters and compare them with import volumes reported by responding exporters at the time of original investigations. Volume of exports made by these exporters is quite low as compared to volume of exports considered for determination of individual normal value and export price on basis of individual questionnaire response.
- xviii. Since export price is the price at which goods have been exported for consumption in Indian market, price at which different buyers in India have purchased the goods from different suppliers from subject country cannot be materially different. Considering the geographical proximity of the subject country there cannot be a material difference in expenses incurred by different producers in Bangladesh. The same is also the practice of the EU and the same practice of giving margins to new shippers which was accorded to non-sampled cooperating exporters in original investigation be followed in the present investigation.
- xix. Authority should restrict the result of investigation to a determination of whether the responding exporter constitutes a new shipper within the meaning of Rule 22.
- xx. Argument of the applicant on the basis of WTO Panel report is misplaced. In that panel report the investigation didn't even undertake sampling. It only provides that absence of any cross-referencing in Article 9.5 of the Agreement shows there is no obligation on Authority to calculate a residual duty margin by giving neutral margin as per Article 9.4. The WTO Panel observation was with regard to obligation on the Authority under a law and that too in an original investigation.
- xxi. The applicant has indulged in suppression of facts and filed incomplete information in the original investigation. Applicant has a related entity, 'Sadat Jute Industries Limited'. It has been claimed that it does not produce Jute Sacking Bag, but only Jute yarn and hence has not submitted questionnaire response. Such information was not disclosed in the original investigation. Despite being a producer/exporter of Jute Yarn/twine, it did not respond to the questionnaire in previous investigation. Despite claiming it to be a producer, the related party did not file a response even in original investigation. In the original investigation exporter clearly stated it does not have any related or subsidiary company involved in the product under consideration.
- xxii. Petitioner has no domestic sales of sacking bags and did not export to India during original investigations yet has significant business interests in India.
- xxiii. Applicant claimed excessive confidentiality without any good cause. It treated such data confidential which is publicly available and sought confidentiality on information such as Memorandum & articles of association, details of ownership, the export documents relating to the exports of the product under investigation made to the Indian customers, the products produced and exported, names and information of the related parties. Non-confidential version of petition and questionnaire response fail to adhere to confidentiality requirements under AD Rules and Trade Notice 1/2013.
- xxiv. Requirements under Rule 22, to prove it has not exported the product in the POI and it is not related to any exporters/producers in the exporting country subject to the duties on the product, have not been fulfilled in the application and it is based on mere statements.
- xxv. The applicant has undertaken ceremonial business in the product under consideration but wishes the authority to determine individual dumping margin.

- xxvi. Applicant is not a new shipper and has exported PUC in the original investigation and attracts anti-dumping duty on a type of the PUC.
- xxvii. Since the authority is investigating circumvention proceedings as well it is important to ascertain whether or not the applicant is exporting Sacking Cloth. It must provide information of Sacking Cloth too, being the circumvented product of Sacking Bag.
- xxviii. No information, evidence and claim by the applicant with regard to appropriateness of normal value and export price. No information has been given on dumping margin. The applicant has restricted itself to filing questionnaire response that is relevant for original investigations.
- xxix. No importers have responded in the current investigation leading to absence of evidence to establish appropriateness of the export price claimed. Furthermore, there is also an absence of bonafide transactions which is vital in current review.
- xxx. The applicant has conveniently referred to the word 'shall', as mentioned under Rule 22 of the Indian Anti-dumping legislation, as per its convenience. However, the word 'shall' has to be read in conjunction with the conditions mentioned therein for initiating a new shipper review.
- xxxi. The investigation can be initiated only when the new shipper has effectively discharged his obligation by demonstrating that the requirements under Rule 22 have been met which in the current case have not been met.

#### 10. Submissions by the Applicant Exporter:

- i. Rule 22 provides that Designated Authority *shall* carry out a review for new shipper. Use of the word 'shall' makes it clear that Rule 22 of the Anti-dumping Rules provides for mandatory initiation of new shipper review i.e. if the conditions prescribed under Rule 22 are met, Designated Authority is required to initiate new shipper review and does not have any discretion in this regard. Thus, the claim of the domestic industry that new shipper review should not be initiated because it is not appropriate in the present case even if the conditions prescribed under Rule 22 are met is contrary to the provisions of Rule 22 of the AD Rules.
- ii. In Anti-dumping Agreement, Article 9.5 makes it mandatory to initiate the new shipper review. The use of the word "shall" under Article 9.5 indicates that there is no room for any discretion for the investigation authority. Thus, if the conditions under Article 9.5 of the anti-dumping agreement are satisfied, it is mandatory for the authority to not only carry out a review but also determine individual margin of dumping for such exporter.
- iii. Domestic industry submits that applicant should not have exported the product under consideration in any form during the investigation period to be eligible for new shipper review. The Designated Authority granted individual rate of duty to various co-operating producers/exporters for each category of product based on exports made by those producers/exporters during the POI. If any producer/exporter had not exported a particular category of product then those producers were subject to residual rate of duty with respect to that particular category. Respondent exported Jute yarn/twine & Hessian Fabrics to India during the POI. However, the Respondent did not export sacking bags during the POI. Accordingly, M/s Janata Jute Mills Ltd. was granted individual anti-dumping duty rates for Jute yarn/twine & Hessian Fabrics but for sacking bags, it was subjected to residual rate of anti-dumping duty.
- iv. It is clear that the anti-dumping investigation comprised of three different product categories and each product category was treated separately for imposition of anti-dumping duty. The Designated Authority did foresee the situation wherein a particular product type was not exported by any producer/exporter. Accordingly, it was duly noted in the final finding as follows:

*"If any product type viz. Yarn/Twine, Sacking Bag or Hessian Fabric has not been exported by any sampled producer/exporter, dumping margin and injury margin as*

*determined for residual category of producers/exporters has been accorded to such producer/exporter for the product type not exported to India during POI. Any producer/Exporter who has not exported during POI can apply for review as per rule 22 of AD rules.*

- v. The aforesaid observation of the Designated Authority in the final finding has already settled that producer/exporter who has not exported a product category during the POI can apply for new shipper review.
- vi. The domestic industry has emphasized that if individual dumping margin is determined for new shipper, it will be unfair to the non-sampled producer/exporter in the original investigation. Thus, when sampling methodology is adopted in the original investigation, new shipper should not be granted individual margin of dumping.
- vii. Firstly, the domestic industry has failed to note second proviso of Rule 17 which provides for determination of individual margin of dumping for even non-sampled producers who submits necessary information. Thus, when the Designated Authority is obliged to consider request for individual margin of dumping for producer or exporter in the same investigation in which methodology for sampling is adopted, there can be no rationale for denying such right to a new exporter in a new shipper review. Thus, no prejudice is caused to non-sampled producer vis-à-vis new shipper.
- viii. Secondly, Rule 17 provides for determination of individual margin of dumping for producer/exporter. However, in case the number of exporters, producers, importers or types of article involved are very large, the authority is allowed to limit its finding to a sample of interested parties. On the other hand, new shipper review, which is carried out under Rule 22 of the Anti-dumping Rules provides for determination individual margin of dumping for the new shipper. Unlike Rule 17, it does not provide for adoption of sampling methodology. There is nothing to suggest that proviso to rule 17 should be superimposed on Rule 22.
- ix. Thirdly, consistent practice of the Authority to interpret Rule 22 to determine individual margin of dumping for exporters is consistent with its obligations under the WTO Anti-dumping Agreement.
- x. Fourthly, it is incorrect to equate new shipper with non-sampled producer/exporter in the original investigation. Unlike non-sampled exporter, new shipper did not export during the original period of investigation and had no opportunity to get selected for individual examination in accordance with Rule 17.
- xi. Lastly, it is not clear why domestic industry is claiming prejudice on behalf of non-sampled exporter.
- xii. Domestic Industry submitted that it is burdensome for the Authority to initiate new shipper reviews for every applicant in the present case. However, the domestic industry cannot decide that conducting new shipper review for more than one exporter is burdensome for the Authority. It is upto the Authority to decide what is burdensome. Also, Rule 22 of the Anti-dumping Rules & Article 9.5 of the Anti-dumping Agreement do not permit for rejection of new shipper review request on the ground that there are many probable exporters seeking new shipper review. In fact, the Designated Authority has conducted as many as eight new shipper review investigations in respect of imports of *Vitrified/Porcelain Tiles from China PR and UAE*. Thus, apprehension of more new shipper review applications cannot be a ground for rejection of new shipper review application and can certainly not be a ground to terminate the review which is already initiated. Lastly, it is noted that rejection of new shipper review on the ground that it is burdensome or that is not appropriate due to any other reasons which is not expressly provided in Article 9.5 of the Anti-dumping Agreement is inconsistent with

the obligations under Article 9.5. Thus, it is clear that there cannot be rejection of new shipper review on the ground that it is burdensome.

- xiii. Domestic industry claims that exporters can request for mid-term review of existing anti-dumping duty if the applicable anti-dumping duty is higher than the current dumping margin. Mid-term review is initiated under Rule 23 of the Anti-dumping Rules if there is change in circumstances, which are long-lasting in nature. There is no claim regarding change in circumstances in the present case by the Respondent.
- xiv. A priori denial of de-minimis dumping margin for a new shipper is not permissible. Article 5.8 of the Anti-dumping Agreement and Rule 14(c) of the Anti-Dumping rules provides that there shall be immediate termination of cases where the authorities determined that the margin of dumping is less than two percent i.e. *de minimis*. If there is no individual dumping margin determination for new exporter pursuant to new shipper review then there will be no occasion for application of Article 5.8. Any interpretation that excludes application of the entire provision *a priori* cannot be adopted. It is also not doubted that Article 5.8 [and thereby Rule 41(c) of the Anti-dumping Rules] is applicable in case of new shipper review. Panel in *Canada - Welded Pipes* observed that:

*It seems to us that there is an obvious reason why the relevant parts of Article 5.8 might apply in this context, namely to ensure that new shippers with de minimis margins of dumping are not subject to anti-dumping duties in the same way as exporters examined in the original investigation.*

- xv. Rule 22 (2) provides that the Central Government may resort to provisional assessment for exporter made by the new shipper during the pendency of the new shipper review. NSR investigation was initiated specifically on the import of Jute Sacking Bags by the Designated Authority *vide* initiation notification dated 1<sup>st</sup> January 2018. The relevant para of the initiation notification is as under:  
 “The present investigation relates to proposed exports of Jute Products by M/s Janata Jute Mills Limited (Producer and Exporter) **specifically Jute Sacking Bags** in terms of the application filed before the Authority in accordance with the Act and the AD Rules.” (emphasis added)

- xvi. However, the initiation notice in paragraph 3, the Authority inadvertently noted that:  
**“The Authority recommends provisional assessment on all exports of the subject goods made by M/s Janata Jute Mills Limited till this review is completed,** in accordance with Rule 22 of the AD Rules and having regard to Customs Notification No. 01/2017 – Cus (ADD) dated 5th January, 2017 and Customs Notification No. 11/2017 – Cus (ADD) dated 3rd April, 2017” (emphasis added)
- xvii. Ministry of Finance *vide* Customs Notification No. 30/2018 – Customs (ADD) dated 30<sup>th</sup> May 2018 had notified provisional assessment of the “Jute Products” and thereby includes Jute Yarn/Twine, Hessian Fabric and Sacking Bags. The relevant extracts of the Customs Notification dated 30<sup>th</sup> May 2018 is as under:

“Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid recommendation of the designated authority, hereby orders that pending the outcome of the said review by the designated authority, **the subject goods, when originating in or exported from Bangladesh or Nepal by M/s. Janata Jute Mills Limited (Producer) and imported into India, shall be subjected to provisional assessment till the review is completed**” (emphasis added)

- xviii. Prior to the issuance of customs notification of provisional assessment, Nil rate of duty was applicable for Hessian Fabric and 20.6 USD/MT on jute yarn/twine exported by Janata Jute. However, customs

authorities are also now requiring provisional assessment on imports of these goods exported by Janata Jute and is requesting furnishing of bond & bank guarantee for exports of jute yarn and twine.

- xix. Rule 22 of the Anti-dumping Rules requires provisional assessment of goods in respect of which new shipper review is initiated and not for any other products on which no new shipper review is initiated.
- xx. There is no requirement of provisional assessment for exports of Jute Yarn/Twine and Hessian Fabric made by Janata Jute as the anti-dumping duty is already in force on export of these two products and there is no ongoing new shipper review of anti-dumping duty on these two products for exports made by Janata Jute. Insistence of bank guarantee is putting an onerous burden on the importers and is creating uncertainty about the actual liability of anti-dumping duty on the imports of Jute Yarn/twine and Hessian Fabric. We request the Designated Authority to clarify that new shipper review is initiated for export of Sacking Bags by Janata Jute and therefore provisional assessment is recommended only for import of Sacking Bags in accordance with Rule 22(2) of the Anti-dumping Rules and not for other Jute Products namely Hessian Fabric & Jute Yarn/Twine.
- xxi. The fact that Sadat Jute Industries Ltd. is the related entity of the Respondent and that there is no other related entity of the Respondent in Bangladesh was also clearly submitted by the Respondent in the original investigation. Respondent has also provided complete information regarding its related entity in Bangladesh in the application requesting new shipper review. In the application filed before the Authority, the Respondent has clearly stated:  
*"Sadat Jute Industries Ltd. is the related entity of the Applicant. Sadat Jute Industries does not manufacture sacking bags. It only manufactures jute yarns/twines. The Applicant is not related to any other exporter or producer in Bangladesh or Nepal who are subject to anti-dumping duty."*
- xxii. In order to ensure maximum compliance, the Respondent did file the exporters questionnaire response as per the new format prescribed by the Authority vide Trade Notice dated 28<sup>th</sup> February 2018. All the relevant information such as production process, list of major shareholders, sales route of the PUC to India etc. are provided by the Respondent as part of the questionnaire response.
- xxiii. The domestic industry claims that prospective period of investigation cannot be considered for determination of dumping margin in a new shipper review because it creates possibility of manipulations by the new shipper/exporter. In order to ensure that Respondent has made bona fide sales and there are no manipulations, the Authority can compare the export price of sacking bags exported by Janata Jute prior to the date of initiation of new shipper review i.e. during 1<sup>st</sup> January 2017 to 31<sup>st</sup> December 2017 with the export price of sacking bags exported by Janata Jute after the date of initiation of new shipper review i.e. from 1<sup>st</sup> January 2018 to 30<sup>th</sup> June 2018. We also note that the excerpt from the *Tiles* case cited by the domestic industry refers to an observation of the Hon'ble CESTAT which was discussed by the Hon'ble High Court of Delhi in *H and R Johnson (India) Limited v. Union of India & Ors.* [2008 (232) E.L.T. 390]. The High Court expressed its disapproval of the very same paragraph cited by the domestic industry and noted that in the case of a first-time shipper, a retrospective period cannot be taken. Based on this, the High Court agreed that, with respect to New Shipper Review, a prospective period of investigation must be allowed and cannot be ruled out.
- xxiv. Domestic industry claims that the Respondent has not provided details of its exports prior to the initiation of investigation. Domestic industry relies on the format prescribed by the Authority for initiation of new shipper review. The present investigation was initiated on 1<sup>st</sup> January 2018 i.e. before the Authority prescribed the format for application to be filed new shipper for requesting initiation of new shipper *vide* Trade Notice No. 08/2018 dated 25<sup>th</sup> April 2018. Prior to the issuance of this Trade Notice, there was no application format prescribed by the Authority to request for initiation of such new shipper review. Thus, it is legally incorrect to claim that Respondent has not provided information in accordance with the format prescribed by the Authority.
- xxv. Domestic industry requests the Authority to club all the existing new shipper reviews for administrative convenience. The domestic industry does not provide any legal basis for such request. Authority is required to determine individual margin of dumping for different new shippers if the conditions required under Rule 22 are satisfied. Moreover, six new shipper reviews are already initiated on different dates and are currently at different investigation stage of investigation. POI and

product category for each new shipper review is different. Factual issues arising in these reviews will also be different. Moreover, even though no specific timeline is prescribed under the rules for completion of the review, it is expected that the review is completed in a timely manner. Article 9.5 of the Anti-dumping Agreement, which provides for the new shipper review, specifically provides that new shipper review should be completed on an accelerated basis.

- xxvi. The domestic industry has also claimed that individual export price and dumping margin of new exporters may not be materially different and therefore there is no requirement to conduct new shipper review. This assumption is generic and has no factual basis. In any case, if the export price is not materially different then these exporters would be subjected to the same or similar anti-dumping rate pursuant to the review. It will not cause any prejudice to the interest of the domestic industry.
- xxvii. Domestic industry places reliance on the EU law to submit that in case sampling has been done in the original investigation, then the new shipper must be granted cooperating non-sampled rates rather than individual dumping margin. In addition to this, it is also claimed that the prices at which different buyers in India have purchased the goods from different suppliers in Bangladesh (essentially, export prices) cannot be materially different and therefore, the cooperating non-sampled rate should be applied. It is noted that EU law reproduced by the domestic industry and submit that the provision contained in EU law appears to go beyond the law contained in the ADA. In any case, such commitments are not globally applicable and Indian AD Rules and the Act do not provide for the same. Thus, it is not possible for the Designated Authority to incorporate such provisions of EU law given the clear and unequivocal mandate of the Indian law.
- xxviii. Domestic industry has claimed that Respondent has incorrectly relied on the WTO decision in *Mexico – Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice* to submit that anti-dumping duty rate meant for co-operative non-sampled exporter cannot be granted to new exporter. The Domestic industry has relied on the provision in the EU law and requested the Authority to follow the same practice. In this regard, we submit that Article 9.4 of the Anti-dumping Agreement provides for determination of anti-dumping duty for non-sampled exporters. Article 9.5 of the Anti-dumping Agreement provides for determination of duty for new shipper. Thus, provision governing anti-dumping duty for non-sampled exporters and for new shipper is different and there is no rationale for commingling the two provisions or reading them in a manner that reads into both provisions. There is no legal basis for applying anti-dumping duty rate determined for non-sampled cooperating exporters in accordance Article 9.4 to a new exporter for whom anti-dumping duty is to be determined in accordance with Article 9.5 of the Anti-dumping Agreement. Article 9.5 does not borrow provisions of Article 9.4 and does not incorporate the same by reference. Also, nothing contained in Article 9.5 leads to the deduction that provisions of Article 9.4 can be borrowed for the purpose of Article 9.5.
- xxix. It is submitted that though *Mexico – Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice* arose out of different facts and circumstances, there can be no doubt that the Panel and Appellate Body report is conclusive regarding the legal issue of applicability of sampling provision to new shipper reviews. We reiterate that in the absence of cross referencing in Article 9.5 to Article 9.4 (sampling), there can be no interpretation or expanded reading of the legal provisions as contained under Article 9.5 and resultantly, Rule 22 of the AD Rules.
- xxx. Domestic industry claims that various information such as memorandum and articles of association, details of ownership, the export documents relating to export of the product under investigation, the products produced and exported, name and information of related parties. We submit that such a claim is baseless, and the Respondent has discharged its full responsibility in the matter. It is also submitted that the documents for which confidentiality has been claimed are not public domain documents and contain business confidential information. As per Trade Notice 1/2009 dated 25 March, 2009, the Respondent was required to furnish separate copies of the confidential and non-confidential versions. The same has been done. Based on the distinction between the two versions, the Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information. It is submitted that certain documents, such as Memorandum & Articles of Association of the Respondent, were not susceptible to summarization and the titles of the document are sufficient for understanding the nature / content of the documents. The purpose of providing a non-confidential summary is to ensure that the responding party is enabled to respond to the same and counter any arguments arising from such documents. However, in the present scenario, these documents are provided for the information of the

Designated Authority concerning the authenticity of the Respondent and its legal existence, and not in support of any legal contentions raised.

- xxxi. Domestic industry has sought additional information pertaining to the Respondent's sales of sacking cloth in view of the Anti-Circumvention investigation being undertaken by the Authority. In this regard, it is submitted that the purpose and objective of the new shipper review and the anti-circumvention investigation are completely distinct. It is also submitted that the products examined under the two investigations are also completely distinct. There is no rationale for commingling the two investigations in any manner.
- xxxii. Domestic industry has claimed that the hearing conducted by the Authority is not "effective" in so far as relevant information is filed by the interested parties and made available to all other interested parties. In this regard, it is submitted that all relevant evidence pertaining to the criteria encapsulated in Rule 22 have been supplied to the Authority along with non-confidential versions thereof prior to the oral hearing. All such documents remained available in the public file. Therefore, the claims of the domestic industry are merely statements and merit no consideration at all. We request the Authority to reject such statements.
- xxxiii. Domestic industry claims that the lack of response from importers is evidence that the Respondent has somehow attempted to suppress the fact that a token export was made at unrealistic price in order to obtain a low or no dumping margin and thereafter aggressively dump the volumes. We note that the domestic industry has recorded its theories and made no legal or factual submissions in this paragraph. It is submitted that the neither the Respondent nor the Authority itself can compel an independent importer to participate in an ongoing investigation. Therefore, the lack of such participation does not evidence anything. The domestic industry's submissions are merely accusatory statements and theories with no legal or factual merit. We request the Authority to reject such statements.
- xxxiv. Domestic industry has reiterated its submissions that the low volume of exports by the Respondent shows that the transactions are somehow not *bonafide*. There is no merit in such claims. The Respondent reiterates that the only criteria applicable to new shipper reviews is contained in Rule 22. The attempts to expand Rule 22 by reading in additional criteria regarding "representative" or "sufficient" exports, is illegal and has already been determined to be so by the WTO Panel and Appellate Body in *Mexico – Definitive Anti-dumping Measures on Beef & Rice*.
- xxxv. The domestic industry has requested the Authority for grant of another hearing. We request the Authority to note the vagueness of the submissions made by the domestic industry, its failure to make itself aware of facts and circumstances of the original investigation as recorded in the Final Findings issued by the Authority and its attempts at misguiding the present investigation. We submit that the domestic industry failed to take note of documents supplied by the Respondent herein and which were made available in the Public File by the Authority, prior to the hearing conducted, and is now claiming that the hearing was ineffective because it did not have access to the relevant information.

**11. The submissions made by importer/user (M/s Chiranjilal Gourishanker & Co. and Unnati Overseas) are as follows:**

- **It is noted that similar submissions are made by M/s Golden Floor Furnishing Pvt. Ltd. (importer/user)**
  - i. It is submitted that M/s Janata jute mills limited participated and cooperated in the anti-dumping investigation during the period of investigation. During the period of investigation (1<sup>st</sup> April, 2014 to 31<sup>st</sup> march, 2015), M/s Janata jute mills Limited had only exported Jute Yarn/Twine and Hessian Fabric to India. The Authority evaluated individual dumping margin and recommended individual rate of anti-dumping duty on jute yarn/twine (20.68 US\$/MT) and hessian fabric (Nil Duty) exported by M/s Janata Jute Mills Limited. Since, M/s Janata Jute Mills limited did not export jute sacking bags during the POI, residual rate of anti-dumping duty (138.97 US\$/MT) was applicable on exports of jute sacking bags by Janata Jute Mills Limited to India.
  - ii. M/s Janata jute mills limited applied for a New Shipper Review under Rule 22 of anti-dumping rules for jute sacking bags. NSR investigation was initiated specifically on the import of jute sacking bags by the designated authority vide notification dated 1<sup>st</sup> January, 2018.



- iii. Rule 22 of the Anti-Dumping Rules requires provisional assessment of goods in respect of which NSR is initiated and not for any other products on which no NSR is initiated. Accordingly, the initiation notification issued by the Designated Authority recommended provisional assessment of anti-dumping duty on exports of Jute Sacking bags made by Janata Jute Mills Ltd. till the completion of the New Shipper review.
- iv. Thus, it is clear that provisional assessment was required only for imports of sacking bags from M/s Janata Jute Mills Ltd., for which NSR was initiated and is ongoing. However, ministry of Finance vide Customs Notification No. 30/2018 – Customs (ADD) dated 30<sup>th</sup> May, 2018 had notified provisional assessment of the “Jute Products” including Jute Yarn/Twine, Hessian Fabric and Sacking Bags.
- v. It is submitted that the ministry of finance had inadvertently recommended provisional anti-dumping duty on subject goods i.e. all three jute products namely Jute Yarn/twine, Hessian Fabric and Sacking Bags. Customs authorities are now requesting for a bond/bank guarantee from the importers on imports of Jute Yarn/Twine and Hessian fabric from M/s Janata Jute Mills Ltd. There is no requirement of provisional assessment for exports of Jute Yarn/twine and Hessian Fabric made by Janata Jute Mills Ltd. as the anti-dumping duty is already in force and there is no ongoing NSR of Anti-dumping duty on these Jute products for exports made by Janata Jute Mills Ltd. Insistence of bank guarantee is putting an onerous burden on the importers and is creating uncertainty about the actual liability of anti-dumping duty on the imports of Jute Yarn/Twine and Hessian Fabric.

#### **E. EXAMINATION BY AUTHORITY**

12. Rule 22 of the Anti-Dumping Rules provides as follows –

*“22. Margin of dumping, for exporters not originally investigated.*

*(1) If a product is subject to anti-dumping duties, the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product.*

*(2) The Central Government shall not levy anti-dumping duties under sub-section (1) of section 9A of the Act on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1) of this rule:*

*Provided that the Central Government may resort to provisional assessment and may ask a guarantee from the importer if the designated authority so recommends and if such a review results in a determination of dumping in respect of such products or exporters, it may levy duty in such cases retrospectively from the date of the initiation of the review.”*

13. Article 9.5 of the WTO Agreement states as under –

*“9.5 If a product is subject to anti-dumping duties in an importing Member, the authorities shall promptly carry out a review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to the importing Member during the period of investigation, provided that these exporters or producers can show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product. Such a review shall be initiated and carried out on an accelerated basis, compared to normal duty assessment and review proceedings in the importing Member. No anti-dumping duties shall be levied on imports from such exporters or producers while the review is being carried out. The authorities may, however, withhold appraisement and/or request guarantees to ensure that, should such a review result in a determination of dumping in respect of such producers or exporters, anti-dumping duties can be levied retroactively to the date of the initiation of the review.”*

14. In terms of the aforesaid Rule, provisions in the WTO Agreement and the past practice of DGTR, a New Shipper Review investigation is to be carried out under following circumstances for the purpose of

determining individual dumping margin in respect of any exporter or producer from the subject country attracting ADD:

- i. that the exporter or producer has not exported the product under consideration during the period of investigation, and
  - ii. that exporter or producer shows that they are not related to any of the exporter or producer in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product concerned.
15. In the instant case, M/s Janata Jute Mills Ltd. filed an application before the Authority seeking individual dumping margin on jute sacking bags and requested for initiating the new shipper review.
16. As regards the eligibility of the producer/exporter for claiming 'NSR', the Authority has correlated the claim made by the producer/exporter with respect to data/ information filed by the producer/exporter in the original investigations. No interested party has provided evidence of non-fulfilment of condition by the producer/exporter for NSR by way of any substantive evidence. The Authority therefore holds that the producer/exporter is eligible to seek a New Shipper Review in the instant case.

### **Scope of Investigation**

17. The Authority notes submissions by the importers regarding the field formation interpreting Rule 22 applicability on all three types covered in Product under Consideration in original investigation and clarifies that the scope of product under review from NSR is Jute sacking bags only as stated in Para 1 of the initiation notification dated 1.1.2018. The other two product types i.e. Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single) and Hessian Fabric covered in the PUC in the original investigation are not part of this review and hence the AD duties applicable on these two types will be as stipulated in S. No. 9 and 10 in Custom Notification No. 11/2017-Cus (ADD) dated 3<sup>rd</sup> April, 2017.

### **Determination of Dumping Margin and AD measure**

#### **Normal Value**

18. The producer/exporter has provided Cost of Production (COP) of the subject goods during POI. The Authority has determined ex-factory COP as \*\*\*Taka/MT with addition of 5% profit, the normal value comes to Taka/MT (\*\*\* \$/MT).

#### **Ex-Factory Export Price**

19. The Authority notes that producer/exporter has exported \*\*\* MT during POI at CIF of 82655.66 Taka/MT. After considering adjustments on Inland freight, Port charges and Bank charges to an extent of \*\*\* taka, \*\*\* taka and \*\*\*US\$ respectively for the exports to India. The Ex-EP for the only transaction comes to \*\*\* Taka/MT (\*\*\* \$/MT). The Authority notes that export subsidy claimed as an adjustment for Ex-EP is not admissible as was also held in the original finding in para 127 (v) of Final Finding dated 20<sup>th</sup> October, 2016 being not one of the identified adjustments under Article 2.4. However, appropriateness of this export price is considered below.
20. The Authority notes that the producer/exporter has done only one transaction (export) of sacking bags on 9.2.2017 to India of only \*\*\* MT quantity. In the original investigation, the 2 sampled producer/exporter considered for individual dumping margin had exported much significant quantities i.e. more than 800 MT individually. The non-sampled producers/exporters who had cooperated were accorded dumping margin on the average dumping margin of the 2 sampled producers/exporters. The annual demand of sacking bags in India is the range of almost 50000 MT, therefore establishing that price of a small quantum of consignment is representative requires appropriate analysis.
21. The Authority notes that there is no stipulation on the quantum of exports to be made by a New Shipper during the chosen POI. However for the export price to be representative for the POI, the Quantum and spread of exports should be such that it ensures representativeness, appropriateness and reliability of the export price. The Rule 22 provides for determining individual dumping margin for a New Shipper. The POI chosen may be both historical and prospective as there is no bar in the AD Rules regarding choice of POI. The Hon'ble High Court of Delhi in H and R Johnson (India) Limited vs. Union of India through order dated 14.05.2008 taking cognizance of Hon'ble CESTAT's order dated 27.8.2007 has clarified regarding POI being of a prospective period. In the instant case, the POI considered is both historical and

prospective that too of a sufficient duration, to provide the producer/exporter a reasonable and fair opportunity. The producer/exporter did not export during the post initiation period of POI. The Authority notes that producer/exporter has submitted regarding delay in issuance of Custom Notification under Rule 22 by the Department of Revenue but no details of loss of any confirmed commitment on exports have been stated by the producer/exporter. The trend of past exports and non availment of post initiation period for exports indicates that the producer/exporter not seem to be seriously interested in the Indian market.

22. The Authority notes that the producer/exporter exported only one transaction during the historical period. The Authority in order to establish representativeness of the export price has examined transactions of sacking bags during the same month by other importers and also the average monthly import price of sacking bags during POI from Bangladesh. Comparison on both fronts indicates that there is quite a variation in export prices over time and even types of sacking bags. Since Normal Value has been determined on the basis of Cost of Production for the entire POI i.e. 18 months period, computation of dumping margin by comparing average normal value of 18 months on one hand and with a single export transaction is not reasonable and appropriate.
23. Therefore with only one transaction of a limited quantity of exports, the Authority does not consider it appropriate to accord a specific dumping margin based on this data to the producer/exporter.
24. However, the Authority notes that the producer/exporter has nevertheless shown intent to export and has also undertaken exports though small and therefore Authority accordingly considers AD measure applicable to non-sampled category to applicant producer/exporter rather than the residual category of measure.
25. The Authority notes submissions of both Domestic Industry and the producer/exporter regarding appropriateness in awarding quantum of measure applied for non-sampled producers/exporters to the applicant producer/exporter in a NSR. The Authority appreciates that to the extent possible a NSR applicant needs to be granted an individual dumping margin based on their actual exports during a NSR investigation. However to evaluate this, the producer/exporter needs to export a volume which is of a commercial quantum so as to ensure establishing that the export price to be credible and not tainted. Merely undertaking some token exports does not enable the Authority to establish credibility of the Export Price. The Authority appreciates the submission that had the producer/exporter exported in the original investigation he could have opted for being in sampled category and that the same opportunity needs to be given to him in a NSR investigation. As stated above, such a producer/exporter is provided an opportunity under Rule 22 of AD rules which needs to be seriously availed by the applicant producer/exporter in a manner to establish a justified claim. In event of this not happening the AD measure applicable to non-sampled producers/exporters which are average of sampled producers/exporters would in no way be unfair if applied to the applicant producer/exporter. It needs to be appreciated that the non-sampled producer/exporter could also be either above the aforesaid average level or below it. Therefore for the applicant producer/exporter in the instant case, the same non-sampled category of measure is appropriate and justified.

#### **F. POST DISCLOSURE COMMENTS**

26. M/s TPM representing the domestic industry submitted the following post disclosure comments:
  - (i) An exporter will be eligible for a separate duty only if it has effectively discharged his obligation by demonstrating that the requirements under Rule 22 have been met. It is submitted that it is the exporter applicant that has to show that the mandatory conditions have been fulfilled for an NSR and not the Domestic Industry. There is nothing in the application, written submissions and even in the Disclosure Statement issued which shows that these requirements have been fulfilled. Documents demonstrating eligibility as new shipper review are required by Designated Authority for considering an exporter as a new shipper. It needs to be shown that sufficient sales have been made to establish an appropriate export price.
  - (ii) The domestic industry has extensively submitted in the written submissions the fact that the applicant is a dishonest exporter. In the present investigations, admittedly the applicant has a related entity named 'Sadat Jute Industries Limited'. However it has been claimed

that the said producer does not produce Jute Sacking Bag, it only produces Jute yarn and hence has not submitted questionnaire response. It is pertinent to note here that the applicant did not disclose the facts as regards to its related party in the original investigation. Further, exporter's questionnaire was sent to 'Sadat Jute Industries Limited', a related company of Janata Jute Mills Limited, the responding exporter in the original investigation and the applicant in the instant investigation. However despite being a producer/exporter of Jute Yarn/twine, as has been claimed in the application for the current investigation, 'Sadat' considered it irrelevant to respond to the questionnaire in the previous investigation. There is no mention of 'Sadat' in the original investigation except for the fact that the questionnaire was sent seeking a response but was not replied to. The current application states that 'Sadat' is engaged in the manufacture of Jute Yarn/twine. However, the domestic industry finds it astonishing as to why the said related party avoided filing the questionnaire response in the original investigation when it was engaged in the production of the PUC even at the time of the original investigation. This only implies that in the absence of complete response, the questionnaire response itself in the original investigation was incomplete and the applicant received an individual duty. It was claimed at the time of the oral hearing that the applicant had stated in the original investigation that they have a related party which has not exported subject goods. This is a factually incorrect and misleading statement. Applicant may be put to prove this statement. Relevant page from the non-confidential version of the questionnaire response was earlier enclosed with the written submissions. It would be seen that the exporter clearly stated that it does not have any related or subsidiary company involved in the product under consideration. Appropriate information should have been provided by M/s Sadat Jute Industries Ltd.

(iii) It is submitted that the minimum mandatory information that the new questionnaire for NSR investigation issued by the Authority on 25<sup>th</sup> April, 2018 requires the following:

- a. *Copy of your sales ledger during the POI*
- b. *List of monthly sales per country after the POI*
- c. *Articles of Association/Memorandum of Association*
- d. *Certificate of registration*
- e. *List of major shareholders of the company during the POI*
- f. *Membership certificates (Trade associations etc.)*
- g. *Export licenses, if applicable*
- h. *Production licenses, if applicable*
- i. *Sales routes of the product under consideration to India*
- j. *Production process of the product under consideration*
- k. *Evidence supporting the installed capacity of the plant for PUC*
- l. *Invoicing procedure for the product under consideration*
- m. *Brochure and general company documentation*
- n. *Two sets of export documents to India for exports made after POI and before the POI.*
- o. *Evidence of irrevocable contractual agreements of sales of the product under consideration to India*
- p. *Sample purchase invoices of production equipment for the purpose of manufacture of the product under consideration*

q. *Sample purchase invoices of raw materials used for the purpose of the manufacture of the product under consideration*

- (iv) The mere fact that the authority did not make any specific prescription earlier and has now made specific prescription for the application does not imply that such information is not necessary for the present investigations. It only implies that – (a) this information was required at the stage of petition itself; (b) the requirement lists out very specific document that should be provided to establish the eligibility and (c) the documents that are required by the authority in order to establish eligibility. Thus, the interested party cannot escape the requirement only because it has been listed subsequently. The format is only clarificatory in nature. The format establishes what is considered relevant, appropriate and necessary for the purpose of establishing a case. Thus, insufficient information and evidence has been provided by the applicant.
- (v) NSR pose an inherent risk to a domestic industry that has obtained relief from unfairly traded imports through the imposition of an antidumping duty order. As is often the case, an exporter or producer requests a new shipper review based on one or a handful of high price sales or exports the subject goods during the period of investigation which are not commercially reasonable for a company operating under normal course of trade. The combination of a high “all others” rate and the new shipper’s high price compared to other import prices could mean two things: either the new shipper truly means to replicate the high price sale upon which it predicated the review, or, the new shipper will take advantage of one high price sale to secure a lower-than-average dumping margin, and then typically charge a far lower price (low enough to undercut the competition that has a higher dumping margin, but still high enough to make a hefty profit which would otherwise be unavailable). It needs to be seen whether the sales under consideration is typical and will be representative of the new shipper’s future sales.
- (vi) It needs to be shown that exports made by the new shipper applicant during the period of investigation are sufficient enough to grant dumping margin based on its own normal value and export price. Not only that the exporter had only one export transaction in a product where demand in India is in the region of **13,70,000 MT** (for 18 months of the POI of the present case) and there were at least **322** known export transactions from Bangladesh to India. If exporters from Bangladesh would export **43,626 MT** product during the POI of the original investigations and if there could have been **1,430** transactions in that POI for the product type, it is not normal that the applicants have just one export transaction and wishes the Designated Authority to fix dumping margin on the basis of such export transactions. The concept of ‘bona fide sale’ is necessary to counter attempts at avoidance of anti-dumping duty by undertaking mala fide transactions during POR of new shipper review. The purpose is not to “ascertain the fair value of the merchandise, but examine exports for their commercial reasonableness”.
- (vii) In the instant case, the Authority has noted at para 20 that the exporter has made only one transaction in February 2017. Further the Authority has also observed that the exporter has not made any exports after that and thus it appears that the exporter is not serious about the Indian market. The Authority has also specifically noted as follows:  
*Therefore with only one transaction of a limited quantity of exports, the Authority does not consider it appropriate to accord a specific dumping margin based on this data to the producer/exporter.*
- (viii) Thus, it is apparent that the volumes of exports made by the applicants to India are miserably low having regard to the consumption in India. The exporter must show why it was not able to export higher volumes during the present period. The entire effort is highly stage managed. The transactions done by the applicants were atypical, mala fide

and commercially unreasonable and it follows that the export price depicted by them should not be taken into consideration by the Designated Authority as they do not depict the price at which the applicants will sell PUC in the future. Such export price cannot be established by ceremonial export transactions. Such export price should be considered along with associated volumes having regard to the total imports in India and consumption of the product in the Country. In a situation where there were 13,70,000 MT imports involving 322 transactions, a party cannot contend that it was not able to export significant volumes due to ADD in place. In any case, existence of ADD in place cannot be an excuse for not being able to export. In fact, any argument that a party could not export due to ADD implies that the law presupposes that imposition of ADD shall lead to complete withdrawal of exports from the country concerned. The review should be terminated on the grounds that appropriate export price is not available for comparison and the residual duty should be applied on the applicants.

- (ix) The DI referred to the recent findings in the matter of NSR investigation concerning imports of R-134a, wherein the Authority specifically notes as follows as regards low volume of exports made.

*The applicants have not sold the subject goods in significant volumes vis-à-vis imports from China during the POI even when the applicants were entitled to provisional assessment and other producers/exporters were suffering antidumping duty. They have exported insignificant volumes which does not even merit individual determination. The entire effort in seeking individual dumping margin appears to lack seriousness on the part of exporter to export.*

- (x) There is no questionnaire response from the importers of the PUC. It is from the Disclosure Statement that the domestic industry came to know that importers have made submissions in the present investigation. This further smokes conscious attempt to suppress the fact that a token export was made at unrealistic price in order to obtain a low or no dumping margin and thereafter aggressively dump the volumes. In view of no questionnaire response from the importers, the Designated Authority is prevented from ascertaining appropriateness of the import price. Therefore, absence of importer's questionnaire response is for the reason that the import transaction has been made at officially at normal high price and therefore there is a clear question of the entire case failing if the importer files a questionnaire response and shows the price at which goods were imported. If the goods were imported for trading purposes, the importer would have to show that it has sold the material at a profit considering the import price, it is impossible for an importer to show that it has sold the product at a profit. An importer could not have consumed the product in the market. The importer could have only sold the product in the market. It is only for this reason that there is only one export transaction only to mislead the authority that there is an export price.
- (xi) Grant of dumping margin individual duty based on imports implies correct establishment of normal value and export price. Further, correct establishment of export price requires establishment of reasonableness of the import price. It is not a case where the Authority has granted a past period as the POI and therefore the applicant was not in a position to undertake significant exports because of ADD. It is a case where there are significant imports even after imposition of ADD and the exporter was given a provisional assessment order. Despite an average import of 3,636 MT and 543 MT per month from Bangladesh at the time of original investigation and current POI respectively, the applicant has undertaken a ceremonial export of just 20 MT only. Thus, the applicant in any case has not established that it should be granted individual duty based on its own

dumping margin and grant of individual duty based on sampled cooperating exporters who were earlier investigated by the authority is inappropriate.

- (xii) Notwithstanding, the domestic industry reiterates that the applicant may be given the weighted average duties given to the cooperating companies not included in the sample in the original investigation, since the original investigation involved sampling. Following are pertinent to note in this regard:
- a. The applicant cannot demand a position more advantageous than the cooperating non-sampled producers of original case. If cooperating non-sampled producers were not given individual duties, the NSR applicant cannot insist on duty based on its own data.
  - b. Rule 17 entitles exporters to their own dumping margin. But this right gets superseded/ qualified/restricted by the sampling provision.
  - c. Burden on the Designated Authority is the fundamental justification for sampling and should remain relevant even for NSR.
  - d. Any argument that non granting of individual dumping margin based on their own normal value and export price might lead to exaggerated dumping margin and these exporters may be made to pay a higher quantum of ADD as would have been payable, had that authority considered their own data may not always be true. In fact, there may be situation where the exporter's own data may show higher or lower dumping margin than the dumping margin determined for non-sampled cooperative exporters.
  - e. The NSR limits investigation only to dumping margin. The original duty on non-sampled cooperative producers may even be at injury margin. Thus, extending duty given to non-sampled cooperative producers can also lead to significant balance of interests of the competing interested parties. Thus, balance of convenience suggests that the duty earlier recommended to non-sampled cooperative producers would be just and fair to all parties to the investigations. In any case, it cannot be said that duty recommended on non-sampled cooperative producers at the time of original investigations based on sampling law is illegal, as it exceeds or is lower than actual dumping margin. In fact, duty on non-sampled cooperative producers is imposed even without assessing dumping margin.
  - f. A situation where exporter needs to pay a duty higher than its own dumping margin is addressed in review laws. Thus, the mere fact that a party in the category of non-sampled cooperative producers or NSR may have to pay higher duty than the dumping margin is well addressed under the law. In fact, a party may pay higher or lower duty than the actual dumping margin at the time of shipments. This is however addressed under review provisions.
  - g. Sample was decided by considering various aspects such as volume of imports and product coverage in the original investigation. The dumping margin determined at the time of original investigations is therefore based on a scientifically drawn sample.
  - h. Volume of exports made by the applicant is quite low as compared to total volume of imports of various kinds of jute products in general and sacking bag in particular. While it was appropriate to draw sample at the time of original investigations even when the volumes were low, in case of an NSR, where the POI is partly retrospective and partly prospective, a low volume of exports by the applicant may be insufficient to determine export price.
  - i. Since export price is the price at which goods have been exported for consumption in Indian market, price at which different buyers in India have purchased the goods from different suppliers from subject country cannot be materially different. Considering

the geographical proximity of the subject country there cannot be a material difference in expenses incurred by different producers in Bangladesh. The investigation has however shown that there has been significant variation in terms of export prices of subject goods by all the exporters on monthly basis as well as on transaction wise basis for the month in which the applicant exporter exported goods, i.e., February 2017.

- j. It is also the practice of the EU to grant non sampled cooperative producers to NSR and the said practice has not been held illegal or even inappropriate by a court of law or WTO. While this is EU practice, this is clearly guiding in terms of permissibility of the methodology under the WTO Agreement.

27. M/s LKS representing the producer/exporter submitted the following post disclosure comments:

- (i) The Authority has rejected the export price of Respondent and has not determined individual margin of dumping for the Respondent. The only reason provided by the Authority to support its decision is that Respondent has exported limited quantity of sacking bags *vide* one export transaction during the POI. The Authority has noted that it is fair to extend the anti-dumping duty applicable to non-sampled producer/exporter to the Respondent.
- i. ***Insistence on commercial quantity of exports in a new shipper review for determination of individual margin of dumping is contrary to Rule 22 of the Anti-dumping Rules and Article 9.5 of the Anti-dumping Agreement***
- (ii) In this regard, it is submitted that variation in import price of sacking bags in the same month has no bearing on the credibility or reliability of the export price of the Respondent. The price of Sacking Bags depend on the size/weight/type of stitching and the difficulty in weaving the fabric. Thus, it is expected that selling price by different exporters or purchase price by different importers would show variation even during the same period.
- (iii) Pre-condition that exports should be in commercial quantum and/or should spread over the POI is directly contrary to Rule 22 of the Anti-dumping Rules and Article 9.5 of the Anti-dumping Agreement. Rule 22 of the Anti-dumping Rules states that the Authority shall carry out new shipper review to determine individual margin of dumping if (i) the producer or exporter has not exported the product to India during the period of investigation and (ii) this producer or exporter is not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product. The criteria mentioned in paragraph 1 of Rule 22 are the only criteria applicable to new shipper reviews under Rule 22 of the AD Rules.
- (iv) There is no requirement under Rule 22 that exports by the new shipper should be of certain minimum quantity and/or that such exports should spread over a particular time period to allow determination of individual dumping margin. By so requiring, the Authority has added additional criteria under Rule 22 of “representative” or “sufficient” exports. In other words, by requiring “representativeness” of exports, the Authority has imposed a condition which is not provided in Rule 22.
- (v) In *Mexico –Rice*, Section 89D of Foreign Trade Act (FTA) of Mexico was challenged because Section 89D provided that the volume of exports of the party requesting for new shipper review should be representative. Article 89D permitted the Mexican investigating authority (Economía) to conduct an expedited review provided, *inter-alia*, the respondent exporter shows a “representative” volume of exports to Mexico during the period of review. The Appellate Body therein noted that by so requiring, Article 89D imposes a condition not provided for in the relevant provisions of the Anti-dumping Agreement. As such, Article 89D prevents Economía from granting a review in instances where the conditions set out in the relevant WTO provisions have in fact, been met by a respondent.<sup>1</sup> Consequently, the Appellate Body held that Section 89D of FTA is “as such” inconsistent with Article 9.5.
- (vi) Thus, it is settled that the Authority cannot prevent Respondent from getting an individual dumping margin by adding conditions which are not provided under Rule 22.



**ii. *Anti-dumping duty applicable for non-sampled exporters cannot be applied to a new shipper under Rule 22 of the Anti-dumping Rules***

- (vii) In paragraph 25 of the disclosure statement, the Authority considered the Respondent as a non-sampled producer/exporter and has considered it fair to apply anti-dumping duty rate for non-sampled producer/exporter to the Respondent.
- (viii) Rule 17 of the Anti-dumping Rules provides for individual margin of dumping for exporters but also provides that in case the number of exporters are very large, the authority is allowed to limit its finding to a sample of interested parties. On the other hand, Rule 22 of the Anti-dumping Rules provides for determination individual margin of dumping for a new shipper. Unlike Rule 17, Rule 22 does not contain any proviso and therefore does not permit adoption of sampling methodology in any circumstances. There is nothing to suggest that the sampling proviso to Rule 17 should be superimposed on Rule 22.
- (ix) Likewise, Article 9.4 of the Anti-dumping Agreement provides for determination of anti-dumping duty for non-sampled exporters. Article 9.5 of the AD Agreement on the other hand provides for determination of individual rate of duty for a new shipper. Article 9.5 does not refer to Article 9.4 and rules of Article 9.4 do not apply to Article 9.5. In *Mexico –Rice*, the Panel in para 7.159 of the panel report noted that Article 9.4 of the Anti-Dumping Agreement, which provides for non-sampled anti-dumping duty rate does not apply to new shipper.
- (x) Thus, new exporters and non-sampled exporting producers in the original investigation are not analogous and cannot be equated for the purpose of imposition of anti-dumping duty.

**iii. *Evidence on record suggests that Respondent is interested in the Indian market and seriously availed the opportunity of new shipper review***

- (xi) The Authority has incorrectly observed that the trend of past exports and non-availment of post initiation period for exports indicates that Respondent is not seriously interested in the Indian market. Respondent exported 384 MT of sacking bags to India between 28<sup>th</sup> November 2015 to 14<sup>th</sup> December 2016.
- (xii) The Authority has incorrectly noted that import of 23 MT is insufficient considering the demand of 50,000 MT of Sacking Bags. Demand of 50,000 MT during the POI of the original investigation cannot be compared with the import of 23 MT during the POI of this new shipper review. As per the information available to us through market intelligence, there were insignificant imports of Sacking Bags from Bangladesh during the POI of this new shipper review i.e. from 1<sup>st</sup> January 2017 to 30<sup>th</sup> June 2018. Thus, import of 23 MT by the Respondent is not an insignificant quantity in comparison with the total imports of Sacking Bags during this period.
- (xiii) The Authority has noted the submission of the Respondent that there was delay in issuance of Customs Notification requiring provisional assessment. However, the Authority observes that no details of any loss of any confirmed commitment of exports have been stated. Respondent submits that customer has cancelled order of Sacking Bags pursuant to the imposition of anti-dumping duty on 5 January 2017. Respondent further submits that two purchase orders of Sacking Bags placed by the importer which were eventually cancelled due to the imposition of anti-dumping duty. It is clear that once the anti-dumping duty was imposed, Respondent was not able to secure orders from its customers in India to export higher volume of Sacking Bags. When the new shipper review was initiated on 1<sup>st</sup> January 2018, the Respondent was expecting the issuance of Customs Notification requiring provisional assessment in accordance with Rule 22. However, the Customs Notification requiring provisional assessment was issued only on 30<sup>th</sup> May 2018. Despite serious intent and willingness, Respondent was not able to export sacking bags to India as the anti-dumping duty of 138.97 USD/MT was definitively collected on exports of Sacking Bags even after initiation of new shipper review.
- (xiv) In fact, it would be incorrect on the part of the Respondent to export the subject goods at unfavourable prices by absorbing the anti-dumping duty in order to maximize quantity of exports of Sacking Bags. Respondent did not deviate from its standard practice and exported Sacking Bags to India during the POI only when it was able to obtain suitable price in accordance with market demand.

- (xv) Moreover, the introduction of minimum quantity requirement is against the Authority's own decision in the original investigation. In the POI of original investigation, Respondent exported 6.99 MT of Hessian Fabric by two export transactions. This fact is noted by the Authority at page 45 of the final findings as well. The Authority accepted the Respondent's export price of Hessian Fabric based on these transactions and determined Nil anti-dumping duty rate. Needless to say, export quantity of 6.9 MT was not considered by the Authority as being unrepresentative or unreliable for the purpose of determination of individual dumping margin for the export of Hessian Fabric by the Respondent. Thus, there cannot be any different standard while determining the appropriateness of 23 MT of Sacking Bags in a new shipper review. It is not clear why the Authority has adopted a new and different standard in this new shipper review.
- (xvi) Respondent wishes to highlight that it has extended full co-operation throughout the investigation process and provided all the data and information requested by the Authority. Moreover, the export transaction of 23 MT took place prior to the initiation of new shipper review, which evidences that there is no manipulation of export price. The export price information provided by the Respondent was duly verified by the Authority. Thus, the export price supplied by the Respondent is credible and there is no positive evidence to doubt the correctness or veracity of the information *per se*. Thus, it is clear that the Respondent made *bona fide* sales and seriously availed the opportunity under Rule 22 of the Anti-dumping Rules.
- (xvii) Lastly, Respondent submits that the Authority itself acknowledges that the applicant in a New Shipper Review needs to be granted individual dumping margin. The Authority also notes that the applicant has fulfilled the conditions prescribed under Rule 22. The Authority cannot add further conditions over and above the legal requirements prescribed under Rule 22. Respondent requests the Authority to re-consider its decision and grant individual margin of dumping to the Respondent in accordance with Rule 22 of the Anti-dumping Rules.

#### **G. EXAMINATION BY AUTHORITY :**

- 28. The Authority notes post disclosure comments filed by M/s TPM on behalf of domestic industry and M/s LKS on behalf of M/s. Janata Jute Mills Ltd. (Producer and Exporter). The Authority notes that interested parties have made submissions related to sufficiency of quantity of exports of subject goods i.e. Sacking Bags being considered for NSR made during POI. The Authority notes that M/s LKS has mentioned that in original investigation also only 8 MT of Hessian Fabric was exported and that during this POI, the imports of Sacking Bags on an overall basis is much lower and that 23 MT of exports of Sacking Bags by them is sufficient, in this overall context M/s LKS has further stated that there is no stipulation of any threshold of export quantity in NSR under rule 22.
- 29. The Authority noting the aforesaid submissions holds that nature of enquiry in an original investigation and an NSR cannot be compared on aspects of approach, nature of diligence and analysis undertaken as challenges and constraints in these two investigations are quite different. While there is no threshold prescribed on minimum quantity of exports during POI in NSR under rule 22, it cannot be presumed that Authority will not apply appropriate diligence and approach to establish reasonableness and credibility of export price. One requirement towards this is availability of some reasonable quantity and its reasonable spread over POI for representativeness. The Authority notes the submission of LKS on variation of prices of sacking bags in the month of exports by M/s Janata Jute Mills Ltd. and appreciates that in a month there could be variations in the prices of Sacking Bags due to sizes, type of bag etc. However with the price of sacking bags being denominated on per MT basis, by and large equalizes the size variations. The other major parameter-impacting price could be the count of Yarn used. The usage of Sacking Bags is by and large for packaging applications and so quality variations are not expected to be wide spread. A single transaction of exports in the instant case certainly poses limitation to establish credibility of the export price for the PUC.
- 30. The Authority underscored in an 'NSR', the exporter is aware about the implications of export price on the measure to be recommended on him post exports. There is a challenge before the Authority to establish that the export price is not calibrated and managed but genuine. In case export prices to different customers from different customers are available and that over different time periods of POI, the comparison of these prices with other similar transactions of other exporters enables the Authority in establishing genuineness and reasonableness of export prices. Therefore in the instance case, the

export behaviour of the applicant producer/exporter does not provide the Authority to undertake such an exercise.

31. The Authority notes that though the enabling custom notification of 30.05.2018 under the rule 22 was delayed, the exporter even after issuance of the notification did not export a single transaction. The rule 22 obligates the Authority to determine an individual Dumping Margin only and not the corresponding extent of injury to apply LDR.

### **Conclusions**

32. The Authority therefore holds that in the given circumstances and facts of the case, the producer/exporter can only be considered for an AD measure as recommended for the non-sampled category of exporters in original investigation. This measure is since based on application of lesser duty rule and therefore in the given circumstances, its applicability to the producer/exporter would indeed be fair and appropriate. Accordingly the Authority recommends as under:

### **Recommendation**

33. (i) Entry 47 be added to the existing duty table mentioned in para 132 of the notification no. 14/19/2015-DGAD dated 9/2/2017 (corrigendum to the notification no. 14/19/2015-DGAD dated 20/10/2016) as under:

S. No.	Heading /sub heading	Description of Goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Duty amount	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
47.	5307,5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	In all forms and specification	Bangladesh	Bangladesh	Janata Jute mills Ltd.	Janata Jute mills Ltd	125.21	US\$/MT

- (ii) Exports of Sacking Bags made during POI i.e. 1/1/2017 to 30/6/2018 in accordance with the C.N. No. 30/2018-Customs (ADD) dated 30/5/2018 or not in accordance of this customs notification be regularised in accordance with (i) above. To further clarify the exports of sacking bags made by M/s Janata Jute Mills Limited w.e.f. 1/1/2017 will be subjected to AD duty as stated in (i) above which would be coterminous with the existence of C.N. No. 11/2017-Customs (ADD) dated 3/4/2017.
- (iii) The other subjects goods i.e. Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian Fabric and Jute Sacking Bags and Hessian Fabric if any exported by M/s Janata Jute Mills Ltd. during 1/1/2017 to 30/6/2018 are not part of this NSR and therefore they and their future exports by M/s Janata Jute Mills Limited continue to be governed by the C.N. No. 11/2017-Customs (ADD) dated 3/4/2017.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General